Clause 22, as amended, was added to the Bill.

Clauses 23 to 35 were added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Further discussion on the Finance Bill will be taken up tomorrow. Now, we will proceed to the next item.

---

18 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS INCREASING CUSTOMS DUTY ON CERTAIN ITEMS OF IRON AND STEEL IMPORTED INTO INDIA

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of Notification Nos. 116—Customs to 118—Customs (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 28th April, 1981 together with an explanatory memorandum regarding increase in the Customs Duty on certain items of iron and steel imported into India, under section 159 of the Customs Act, 1962. [*Placed in Library. See* No. LT—2436/81.]

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

SIXTEENTH REPORT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Sir, I beg to present the Sixteenth Report of the Business Advisory Committee.

18.02 hrs.

DISCUSSION RE. ATROCITIES ON ADVISIS IN DIFFERENT PARTS OF THE COUNTRY

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we take up Discussion under Rule 193. Shri George Fernandes.

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) उपाध्यक्ष महोदय, इसी महीने की 20 तारीख को आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के इन्द्रवल्ली गांव में जो पुलिस के द्वारा आदिवासियों की हत्या की गई, उस संदर्भ में आज सदन में यह बहस हो रही है।

पिछले कई दिनों से—असल में एक अरसे से—इस इलाके में रहने वाले आदिवासियों पर संगठित ढंग से जुल्म होता रहा है। आदिवासी न सिर्फ इस आदिलाबाद के इलाके में रहते हैं, बल्कि जो गोंड समाज के लोग देश के इस विभाग में हैं, वे पड़ोस के महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में, जो आदिलाबाद से सटा हुआ जिला है, और इधर मध्य प्रदेश में भी उससे सटे हुए कुछ इलाके में रहते हैं।

18.03 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*].

आन्ध्र प्रदेश में इन लोगों के द्वारा एक अरसे से आन्दोलन चलता रहा, विशेषकर इस बात पर कि गैर-आदिवासियों द्वारा एक जमाने से उनकी जो जमीन छीन ली गई है, वह उनको वापस मिले। एक कानून भी बना, लेकिन उस कानून को अमल में लाने की बात कभी नहीं हुई और कानून के बावजूद आदिवासियों का शोषण उस इलाके में पिछले एक जमाने से ज्यों का त्यों जारी रहा। कई राजनैतिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आदिवासयों की इस समस्या को ले कर उस इलाके में संगठनों को खड़ा किया—कोई एक संगठन नहीं है, अनेक संगठन हैं। कई जगहों पर ये संगठन गांव गांव में हैं, मगर उन लोगों ने आम तौर पर इन संगठनों को गिरिजन

[श्री जार्ज फर्नाण्डीज]

रहतु कुली संगम के नाम से चलाना पसन्द किया, ताकि आदिवासियों के लिए ही यह संगठन है, यह बात स्पष्ट हो, और आम तौर पर जो भूमिहीन खेत-मजदूरों का संघर्ष चलता है, उसमें और आदिवासियों की छीनी हुई जमीन उनको वापस मिले, और बना हुआ कानून अमल में आए, इसके लिए चलाए जाने वाले आन्दोलन में जो फर्क है, वह हमेशा लोगों के सामने रहे।

20 अप्रैल को इन्द्रवल्ली में इस कुली संगम की ओर से एक सभा आयोजित की गई। सभा के आयोजन के बारे में पहले से जानकारी दी गई थी, एलान हो चुका था और सभा की बहुत तैयारी हो गई थी। लेकिन जिन लोगों ने इन आदिवासियों की जमीन एक अरसे से छीन ली है और जिन लोगों ने वह जमीन उन को वापस न मिले इस के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी है, ऐसे लोगों की ओर से एक दूसरी सभा उसी दिन बुलाने का फैसला वहां हुआ। एक संगठन भी खड़ा हो गया जैसे कि ऐसे मौके पर संगठन खड़े हो जाते हैं और रयत प्रोटेक्शन संगम--किसानों का बचाव करने वाले--यह इस संस्था का नाम दे कर उस संस्था की ओर से उसी दिन उसी गांव में एक और सभा बुलाने का एलान किया गया।

अब इस बात को हम लोगों को ठीक समझना चाहिए कि हजारों गिरिजन, कानून का अमल होना चाहिए इस के लिए एक सभा का आयोजन अपनी संस्था की ओर से करते हैं। जिलाधिकारियों को उस की जानकारी है, पुलिस को उस की जानकारी है और मैं मानता हूं कि सरकार को भी उस की जानकारी रहती है क्योंकि आन्ध्र प्रदेश में इस प्रकार का आन्दोलन एक जमाने से किसी ने किसी रूप में चलता रहा है और सरकार की दृष्टि इस आन्दोलन के बारे में बहुत अच्छी नहीं रही है। आप को याद होगा 1978 में एक ऐमनेस्टी इंटरनेशनल ने आन्ध्र प्रदेश की ऐसी घटनाओं को ले कर विशेष जांच की थी और जहां तक मेरी समझ है सितम्बर 1978 में ऐमनेस्टी ने अपनी रपट सरकार को भेजी थी जिस में आरोप लगाया था कि 73 से ले कर 77 तक के चार वर्षों में 300 और 500 के बीच लोगों को जान से मारा गया था आन्ध्र प्रदेश में इसी नाम पर कि पुलिस और लोगों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इसलिए सरकार वहां पर जहां गिरिजन, जहां आदिवासी, जहां खेत मजदूर अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं एक अरसे से बहुत जागरूक रहती है, उन लोगों के बचाव के लिए नहीं जिन के लिए कानून बनाए मगर कानून अमल में नहीं आए, जिन लोगों को कानून के अमल होने से परेशानी महसूस होगी, उन लोगों के समर्थन के लिए वह तैयार रहती है। इन्द्रवल्ली में भी वही हुआ। पुलिस का फर्ज था, जिला प्रशासन का फर्ज था कि जो गिरिजन, जो आदिवासी कानून पर अमल हो इस के लिए सभा करने बैठे हैं उन्हें सभा करने की इजाजत दी जाय। उन की बात को सरकार के सामने, प्रशासन के सामने रखना चाहिए था कि उन की बात को सुना जाय और समझा जाय और अगर जमींदारों का जो किसानों के संरक्षण के लिए संगम बना था उन लोगों को अगर अपने हक के बारे में कोई एक राय रखने की जरूरत थी तो मैं यह मानता हूं कि जिला प्रशासन का यह फर्ज था कि उन्हें मीटिंग के लिए दूसरे दिन समय देते अथवा कोई भी इंतजाम करते कि जिस

से जहां गिरिजनों की सभा हो रही है उन की अपनी शिकायतों को ले कर उस से कुछ दूर की जगह पर उन की सभा हो जाये जिन को कि गिरिजनों की इस मांग से परेशानी थी। मगर जिला प्रशासन यह नहीं करता है। उलटे, इस बहाने कि इस बचाव समिति की ओर से एक अलग सभा आयोजित की गई है। और दोनों सभायें होने से कानून-व्यवस्था भंग हो सकती है, इसलिए जिला प्रशासन सभाबन्दी का हुक्म जारी करता है। हजारों आदिवासी जो उस सभा के लिए वहां पर आए थे वे अपने अधिकारों के लिए जुलूस निकालने का काम जब करते हैं तब उन पर बिना कोई वजह गोली चलाकर, जैसी कि रिपोर्ट है जिसको कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने स्वीकार किया है, उसके अनुसार 14 गिरिजनों को जान से मार डालने का काम किया गया और अनेक लोग घायल कर दिए गए।

प्रदर्शन रोज होते हैं, इस राजधानी में भी रोज होते हैं और प्रदर्शनों को किस तरह से सम्हाला जाए इसके बारे में, मैं मानता हूं जिला प्रशासन और पुलिस कुछ जानकारी रखती है। दिल्ली में संसद के सामने रोज प्रदर्शन होते हैं। काल भी एक प्रदर्शन अलग सूबा मांगने वालों की तरफ से हो गया जिसमें पुलिस ने गिरफ्तारी की, जेल ले जाने का काम किया और एक महीने की सजा सुनाने का आदेश भी हुआ। कुछ दिनों पहले कई और समस्याओं को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर संसद के सामने प्रदर्शन हुआ था जिसमें लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक दिन की सजा सुनाने का काम भी किया गया। कल-परसों से हम यह भी सुन रहे हैं कि आरक्षण के विरोध में इस सदन के बाहर एक प्रदर्शन होने वाला है और सरकार की भी उन लोगों के प्रति इतनी अच्छी भावना है कि उन्हें विशेष रेल सुविधा देकर दिल्ली तक पहुंचाने का काम भी हो रहा है ताकि प्रदर्शन हो जाए। इसके साथ साथ दूसरे लोगों के प्रदर्शनों के बारे में सरकार दूसरा रुख अख्तियार करती है। यहां पर तो सवाल है उन गिरिजनों का, उन आदिवासियों का जिनकी जमीनों को गैर-हरिजनों और गैर-आदिवासियों ने पिछले जमाने से छीन लिया था और आज राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों पर अमल करने के लिए उन गिरिजनों की ओर से प्रदर्शन हो रहा था। कई जिम्मेदार लोगों का तो यह भी कहना है कि जो दूसरी सभा का इन्तजाम हुआ वह जिला प्रशासन के लोगों के कहने पर हुआ था। इस प्रकार से दोनों पर समाबन्दी लागू कर के बिला वजह गोली चलाकर गिरिजनों को मारने और उनको दबाने का काम किया गया। यह सवाल सिर्फ इन्द्रावली का ही नहीं है, एक जमाने से हम इस स्थिति को देखते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले बिहार के गुवा में, जहां आदिवासियों ने यह मांग की थी कि जंगल में उन्हें रहने और पेड़ों से जो भी जिन्दगी वे चला सकते हैं उनको चलाने का अधिकार दिया जाए तो बिहार मिलिट्री पुलिस की ओर से उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई। इसी प्रकार से कुछ दिनों पहले इसी सदन में बहस के दौरान इसका भी जिक्र हुआ कि एक मजदूर नेता जिसका नाम शंकर गुहानिया था, उसकी गिरफ्तारी इसलिए हो गई थी कि उसने अपने दल में डल्ली राजहाड़ा, जिला दुर्ग के आदिवासियों को संगठित करके शराब के नशे से दूर करने का काम किया था जिसके फलस्वरूप जिस व्यक्ति ने 17 लाख का शराब का ठेका लिया था वह पिछले साल में केवल 4 लाख रुपए की शराब ही बेच

[श्री जार्ज फर्नाण्डीस]

पाया। तो उस व्यक्ति को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार करने का काम हुआ और वहां पर मजदूरों को किसी न किसी रूप में सताने का यह सिलसिला चला ।

महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, बम्बई के बगल में थाने में, धूलिया जाने की जरूरत नहीं, जहां भील और बरली लोग रहते हैं, जिनके जंगलों को वहां के साहूकारों ने छीनकर एक अर्से से इन लोगों को और जंगल के भीतर भेजने का और उनके शोषण का काम किया है। वहां की भूमिसेना और कष्टगरी संगठन जैसी संस्था ने, वे आदिवासी जो संगठित होकर न्याय की आवाज उठा रहे हैं, उनको मारने का काम किया। इसी इन्द्रावल्ली के बगल में एक ऐसी घटना घटी, जो महाराष्ट्र के लिए अनुभव रहा। वहां का एक लड़का, जिसका नाम श्री पेत्ती शंकर, इलाहबाद जिले का 23 साल का नौजवान, कालेज में पढ़ा-लिखा, वह गौंड गिरिजन को संगठित करके, उनको इन्साफ मिलना चाहिए, प्रयास कर रहा था, तो महाराष्ट्र और आन्ध्र पुलिस, दोनों ने मिलकर, महाराष्ट्र के भीतर चन्द्रपुर जिले में मोहनबिनपेट्टा नाम के छोटे से गांव में उसे जान से मारने का काम किया। सभापति जी, ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनको हम दे सकते हैं, लेकिन उन उदाहरणों को देने से कोई बात नहीं बनेगी।

सवाल यह है कि आदिवासियों को आज जो स्थिति बनी है, इसको किस तरह से सरकार की तरफ से और समाज की तरफ से हल करना है, इस पर विचार करना चाहिए। स्थिति कितनी बिगड़ रही है, इसका एक विशेष उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हिन्दुस्तान के बहुत बड़े पत्रकार, श्री प्राण चोपड़ा, अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गए थे। बांदा जिले में जिस गांव की स्थिति को देखने गए थे, उस गांव का नाम है—पडरिया, जहां आदिवासी रहते हैं। इस संबंध में उन्होंने 13 अप्रैल के टाइम्स आफ इंडिया के पहले पन्ने पर लिखा है कि जब मैं उस गांव में गया, तो वहां एक ठेकेदार आदिवासी क्षेत्र के बीच में कन्धे पर बन्दूक लगाकर घूम रहा था। प्राण चोपड़ा उनको रोकते हैं और पूछते हैं कि अगर आप बन्दूक इस तरह से लगा कर जा रहे हैं, तो क्या कभी इसका इस्तेमाल भी करते हैं? हां—मैं इस्तेमाल करता हूं। मैं अभी आपके ऊपर भी कर सकता हूं, आपको मैं लूट सकता हूं और मेरा यहां कोई बिगाड़ नहीं सकता है।

'When I asked him whether the Law bothered him much?' he said: "If I strip you of all you have, here no one around here will give any evidence against me."

When he was asked: "Had you used your gun lately on any one?" he replied;

and under quote and unquote Mr. Pran Chopra publishes the reply:

"I have recently killed three persons".

And when Pran Chopra asked him: 'Why?' The answer is:

"It was God's will. He called them."

बन्दूक के साथ उसकी तसवीर को प्राण चोपड़ा ने खींच लिया, गांव के अन्य लोगों और मुखिया के साथ। हमने इस पर गृह मंत्री को भी पत्र लिखा। 13 तारीख

को यह खबर छपी और 15 तारीख को हमने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा और कहा कि इस पर आपको कुछ करना चाहिए। जब एक व्यक्ति स्वयं कहता है और वह भी आदिवासी गांव में खड़े होकर कि अभी अभी तीन लोगों को उसने मारा, चूंकि उनका वक्त आ गया था, लेकिन उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। मुझे पता नहीं गृह मंत्री जी ने इस पर कदम उठाया है या कोई भी बात की, लेकिन स्थिति जैसी है, उसको हम लोगों को समझना चाहिए और सारे देश के कोने-कोने में पूर्वांचल सीमा तक आदिवासियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है और जिस तरह से उनकी पिटाई हो रही है, उसको हम लोगों को समझने को कोशिश करनी चाहिए। 33 वर्ष पहले 1948 में इस देश के प्रधान मंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू थे, उन्होंने इन आदिवासियों की समस्याओं पर कुछ बातें कहीं थीं, आज मैं उन बातों को इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस लिए रखना चाहता हूं कि जब गृह मंत्री जी और यह सदन इस पर विचार करे तो इस समस्या को किसी दल की दृष्टि से न देखते हुए, 1948 में तत्कालीन प्रधान मंत्री ने इन आदिवासियों के बारे में क्या भूमिका हम लोगों के सामने रखी थी, उन के लिए कौन से कार्यक्रम अमल में लाने चाहिए, इस बारे में जो राय व्यक्त की थी, जो सूचना देश के सामने रखी थीं उस को आप के सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने पांच बातें "पंचशील" के नाम से रखी थीं जो इस तरह से हैं—

1. इस देश के आदिवासियों को उन्हीं की अपनी बुद्धि के अनुसार अपने इलाके में विकास करने के लिए मौका देना चाहिए और बाहर से किसी भी प्रकार का हथियार उन के ऊपर डालने का काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए।

2. जंगलों की जमीनों पर एक जमाने से उन का अपना अधिकार है और चूंकि ये लोग जंगलों में ही बसने वाले हैं, इस लिए उस अधिकार को हम लोगों को मानना चाहिए।

3. हमें ऐसे लोगों का एक दस्ता बनाना चाहिए जो आदिवासियों के बीच में विशेष रूप से काम करे और उन्हीं में से ऐसे लोगों को लें जो उनकी समस्याओं को हल करने में योगदान दे सकें।

4. इन के इलाके में बाहरी लोगों को बड़े पैमाने पर नहीं जाने देना चाहिए और उन्हीं में एक समय से चली हुई संस्थाओं के माध्यम से उनके बीच में हम लोगों को काम करना चाहिए।

5. कितना पैसा उन इलाकों में हम लोगों ने खर्च किया है—इस प्रकार के आंकडो में न जाते हुए—इस समाज के लोगों को स्वयं अपना चरित्र बनाकर देश में अपना विकास करने के लिए हम लोगों को मौका देना चाहिए और इसी आधार पर हम लोगों को उन के बीच में काम करना चाहिए।

मैं आज गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा—33 वर्षों की आजादी के बाद और इन पांच सूत्री कार्यक्रम को दृष्टि में रखते हुए आदिवासियों की स्थिति को सुधारने के लिए कहां तक अमल हुआ है। हम ने अब तक उन का सुधार करने का क्या प्रयास किया है? आर्थिक क्षेत्र में हम लोग क्या सुधार कर पाये हैं? हमारे पास ये सरकारी आंकड़े हैं—ये 1977 तक के हैं और उस के

[श्री जार्ज फर्नाण्डीस]

बाद स्थिति में कोई बहुत बड़ा फर्क हुआ हो, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जहां तक नौकरियों का सवाल है—इस देश में आदिवासियों की आबादी 7 प्रतिशत है—लेकिन सरकारी नौकरियों में, विशेष कर एक दर्जे की नौकरी में, उन का प्रतिशत 0.7 है, जब कि उनको 7 प्रतिशत नौकरी मिलनी चाहिए थी। सरकारी प्रतिष्ठानों में तो इससे भी खराब स्थिति है—1976 के अन्त तक सरकारी प्रतिष्ठानों में आदिवासियों का क्लास 1 में प्रतिशत 0.3 था, क्लास 2 में 0.5 था। जहां तक सरकार की तरफ से चलाई जाने वाले नेशनलाइज्ड बैंकस का सवाल है, आप को सुनकर आश्चर्य होगा अफसरों की जगह पर 0.1 प्रतिशत यानी हजार में 1 आदमी को काम दिया गया है, क्लर्क की जगह पर भी 0.8 प्रतिशत लोगों को नौकरी दे पाये हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में जो उनका विकास करने की जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी से समाज भागा है और सरकार कुछ कदम उन के उत्थान के लिए नहीं उठा पाई है। उनका शोषण उस क्षेत्र में ज्यों का त्यों जारी है। मैं इस सम्बन्ध में एक बात और रखना चाहूंगा। हम लोग यह मान कर चलते हैं कि अगर इन लोगों को काम देने की बात करनी है, तो समाज में जा कर किसी एक व्यक्ति को पकड़ कर आप इन को काम देने की व्यवस्था नहीं कर सकते बल्कि पूरे विभाग को इन का विकास करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।

हम को अफसोस है, हम ने कुछ दिन पहले वित्त मंत्री जी से एक प्रश्न यह पूछा था कि हिन्दुस्तान के हर जिले के बैंकों में जमा-राशि कितनी है और उस जिले के विकास के लिए, कर्ज के रूप में उस में से कितना पैसा दिया गया है। इसका जो जवाब मुझे मिला, उस को सुन कर सभापति महोदय, आप को भी धक्का लगेगा। हमारा जो पूर्वांचल का इलाका है, वह सम्पूर्णतया आदिवासियों का इलाका है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय आदि ये सारे जो इलाके हैं, ये सब पूर्णतया आदिवासी इलाके हैं हालांकि इनके बारे में सोच-विचार बहुत कम होता है। यह दस्तावेज इस सदन में, माननीय मंत्री जी ने मेरे एक प्रश्न के जवाब में कुछ दिन पहले दिया था। आप को सुनकर आश्चर्य होगा कि अरूणाचल प्रदेश, इस गरीब प्रदेश में सरकारी बैंकों में जो जमा राशि है, वह 6 करोड़ 69 लाख रुपये है और इन 6 करोड़ 69 लाख रुपये में से उस प्रदेश के लोगों के विकास के लिए कर्ज के रुप में केवल 57 लाख रुपये दिए गये हैं। मिजोरम में बैंकों में जमा-राशि 3 करोड़ 40 लाख रुपये हैं लेकिन कर्जे के रूप में जो दिया है वह 25 लाख रूपये हैं। नागालैंड में जमा-राशि 15 करोड़ 56 लाख रुपये है और कर्जे के रूप में जो दिया है वह 3 करोड़ 53 लाख रुपये है। मैं अनेक उदाहरण अलग अलग इलाकों के दे सकता हूं। इस से भी खराब स्थिति इन आदिवासी इलाकों की आप को देखने को मिलेगी।

इसलिए मैं समाप्त करूंगा इस आग्रह के साथ और सदन में अपनी यह बात रख कर कि आदिवासियों के विकास की दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से जो विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता है, उस के लिए अविलम्ब कदम उठाने का काम होना चाहिए और सरकार को इस सदन के सामने और देश के सामने वह कार्यक्रम रखना चाहिए।

नं० 2, आदिवासियों की जो सामाजिक स्थिति है, जिस सामाजिक स्थिति

की हिन्दुस्तान में कल के अखबारों में चर्चा हुई है कि महिलाओं को किस तरह से बेचा जाता है, जैसे पहली बार यह घटना घटी है, जैसे पहली बार इन को बेचा गया है, अकेले राजस्थान के इलाके में जाने की जरूरत नहीं है; समूचे हिन्दुस्तान में यह स्थिति है और इस हालत में आदिवासी महिलाओं की जो जिन्दगी है, उस समाज के लोगों की जो जिन्दगी है, उन का सामाजिक स्थिति को सुधारने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाने का काम होना चाहिए। इसके साथ ही मुख्तः आज की स्थिति में उन का जान और माल इन दानों के बचाओं का दृष्टि से हम यह अपेक्षा करेंगे कि सरकार कुछ निश्चित और कुछ ठोस कार्यक्रम इस बारे में रखने का भी काम करेगी और इसी उम्मीद से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI UTTAM RATHOD (Hingoli): Mr. Chairman, I am grateful to Mr. George Fernandes for bringing this important thing before the House. Myself and Mr. Narsimha Reddy, we two members come from Adilabad District. We have been associated with tribal taluka in which this Indravalli village is situated.

I remember to have visited this village three or four times during some past years and according to me the population of this village is almost between four to five thousand. It is most unfortunate that in this tribal taluka such an incident should have taken place.

I will take you back. In 1936, 1937 the erstwhile Nizam Government had started a scheme with Baron Heinandors as the head and Grigson as the Revenue Minister to support him, for the upliftment of the tribals in the old Hyderabad State. In those days there were 11 tribal communities in old Hyderabad State and books specially written in Devanagari and Telugu in their tribal dialects were published. Some boys who had studied up to the third or fourth standard were collected at Marlawai by Baron Heinandors, they were brought—especially Gonds—and they were given comprehensive education for a period of three or four years and they were trained and sent to open schools in Gondwaris and Gondpuras. Not only that. The old Hyderabad Government started the upliftment of tribals. Mr. Grigson saw that special social welfare officers were appointed with revenue, judicial and executive powers to give justice to those tribals. And what did I see during my time about these special social welfare officers? They are empowered to give patta lands, patta rights to any tribal. They could impart justice. Certain sections of criminal Procedure Code and the Indian Penal Code were entrusted to them. Not only that, they could extern any moneylender, any miscreant, any non-tribal from that tribal area and ask him to go away from that area. In September 1948 after we got our freedom—I am sorry to say—the tribal development movement has received a set back. I have stayed there till 1957. I say, that when I left Adilabad there was only one road which linked Gudihatnoor, Utnoor and Kerimeri on the other side. Asifabad. After that only two roads have been completed and recently when we have come across a Press note, we were told that this area still remains to be unaccessible. Why? During the last 30 years you could not construct roads there.

Why do you forget that in 1953-54 when in Nalgonda such activities were started by the communist parties, especially in Nalgonda and Khammam areas, we have seen that roads were laid there, so that they could be made accessible and Government machinery could reach there. But this particular Utnoor taluka was completely neglected. But for Mr. Narasimha Reddy

(Shri Uttam Rathod.)

I do not think that even the other village roads could have been constructed there. This Utnoor taluka was completely neglected. I will tell you. According to 1941 census the total population of Utnoor taluka was only 26,000. Out of 26,000 21,900 were tribal Gonds and the other 5,000 were non-tribals. Some of them were Lambadas and some of them were Muslims and others. Due to the Area Restriction Act which we passed here, the Lambadas and others were also included in the list of scheduled tribals in Andhra Pradesh. This is how they got their rights. Today there is an attempt on the part of some political parties to create enmity between these two tribals and see that they fight among themselves so that the others get the benefit of it. It is most dangerous. There is no Government machinery to explain these things to those people. That is the most unfortunate part. I had lived in that area. I worked in that area. What I feel is that an incident where 15 people were killed should not have occurred there. It is not a couple of people. I know the Gonds there. I know the Lambadas. I know the Mathuras there. They are most docile people. I think the Police have taken the law into their hands and they have butchered these people. Unfortunately the Press release says—where the Home Minister says—that a magisterial enquiry has been ordered. I do not know why a magisterial enquiry has been ordered into such a big incident. It must be a judicial enquiry and the head of that commission should be a person of not less than a High Court Judge. I have faced a judicial enquiry in Kinwat firing. A sessions judge as appointed. The enquiry started after one and a half years. The witnesses who had filed affidavits had forgotten about it. Ultimate result was that everybody was set free. I want that a judicial enquiry should be instituted with a High Court judge. Secondly, the Government generally does not take any step against the guilty officers. After the report is presented, it should come up before the House, within six months. They are discussed in the House. But we find that Government generally does not take any action against the guilty people. I say that whenever there is firing on scheduled castes, scheduled tribes, nomadic tribes *Vimukta Jatis* and ex-criminal tribes, Government should take some steps against the guilty officials.

Development activity in the tribal area should be speeded up. I have seen the press release. I am told that Rs. 80 lakhs have been sanctioned. Rs. 80 lakhs are not sufficient. You must send dedicated people there, officers who can identify themselves with the tribals. Missionaries have done it in Poorvanchal, as Mr. George Fernandes said. We had a set of officers during Heimandorf's time. We had an Anthropology M.A. who was not taught in the class room, but he lived with the tribals, drank with the tribals, danced with the tribals. They were the first set of people who were appointed as Social Welfare Officers. Hyderabad was the first State which had a Director of Social Welfare. It was also the first State which bifurcated Tribal Welfare from Social Welfare. Much could have been done, but it is not being done. We are looking to the demands of urban people. Adilabad has been developed, Nirmal has been developed. Even small places like Ichoda and Boath have been developed. But Utnoor is neglected. Who is responsible for deforestation? It is the big contractors. The tribal will fell one tree and he cannot sell it.

In the terms of reference I want the following to be included:

"Whether land regulation was properly implemented?

Whether the tribals were really dealing in timber."

"These two matters should be investigated and those who are found guilty should be punished.

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति जी, मुझ जैसे कमजोर आदमी के दिल में भी कुछ जोश आया है और मैं बड़ा आभारी हूं उस कांग्रेसी मेंबर लोकसभा का, जिसने बड़ी दिलेरी के साथ चाहे, किसी भी वजह से हो, हमारे गृह-मंत्री से इस्तीफा मांगा है ? तो मेरे जैसे कमजोर आदमी के दिमाग में भी आया. . . ।

एक माननीय सदस्य : कब मांगा :

श्री मनीराम बागड़ी : सुबह मांगा है उन्होंने इस्तीफा मांगा है भारत के प्रधानमंत्री की जिंदगी को खतरे की बात पर । इस बात पर उन्होंने ज्ञानी जी से इस्तीफा मांगा है तो हम में भी हिम्मत आई । मौत तो हम किसी की नहीं चाहते और कोई भी नहीं चाहता, लेकिन मौत के खतरे की वजह से अगर इस्तीफा मांगा जा सकता है तो इंद्रावली में 14 आदिवासियों को कत्ल किया गया है, आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है, तो क्या इस पर सरकार को इस्तीफा नहीं देना चाहिए । अब हम में हिम्मत आई है कि 14 आदमियों को कातिल आपकी सरकार, चाहे वह आंध्र-प्रदेश में कत्ल हुए हों, वहां पर भी आप की सरकार है और इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए । मैं उदाहरण देता हूं । 1954 में डा० राम मनोहर लोहिया, समाजवादी नेता ने त्रावणकोर कोचीन में जब तीन आदमी वहां की समाजवादी सरकार ने गोली मार दिए थे, मजदूरों के जलूस पर गोली चलाई थी तो उस सरकार को तोड़ दिया था । सरकार चाहे आप की हो या किसी दूसरे की इंसानी जिन्दगी को कद्र होनी चाहिए । यह 1954 की बात है । आज 1981 है । किन लोगों को हत्या हुई है ? उनकी हुई है जो हजारो सालों से जुल्मों के शिकार हैं, जो मजलूम हैं । उनको मारा जा रहा है । समुचय में उनकी आबादी पांच करोड़ है । सात परसेंट उनको आप रिजवेशन देते हैं । आप उनकी तरक्की करना चाहते हैं, यह उच्च वर्गीय समाज, यह उच्च वर्णीय समाज उनके साथ तरह तरह की ज्यादतियां करता है, तरह तरह के जुल्म उन पर ढहाता है । मैं नहीं चाहता कि बड़े से बड़े गुनाह करने वाले पर भी गोली चले । विनोबा जी जब मंदिर में गये तो उनको वहां से निकाल दिया जाए और तब न गोली चलाई जाए और न लाठी यह बात मैं समझ सकता हूं । बड़े से बड़ा कुकर्म कोई करता है तो गोली नहीं चल सकती है । लेकिन भारत का भूखा नंगा इंसान हजारों साल से मजलूम इंसान अगर कभी करवट लेता है और अपनी बात कहता है तो उस पर गोली चलाई जाए और उसकी जान ले ली जाए, इसको कभी बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। अचम्भा तो तब होता है जब कोई पूछने वाला नहीं होता है ।

नारी की इज्जत समान रूप से होनी चाहिए । वह राष्ट्र की नारी है, समुचय समाज की नारी है । लेकिन अगर नारी की इज्जत होती देखना चाहते हो तो जाओ थानों में और देखो कि आदिवासियों की औरतों की, खानाबदोश लोगों की, सांसी , बीहरा, कंजर, भील, मीना, सपेरा आदि जितने भी ये लोग हैं उनकी औरतें थानों में बैठी हैं और जब पूछा जाता है कि इनको थानों में क्यों बैठा रखा है तो कहा जाता है कि ये औरतें नहीं हैं, ये तो खानाबदोश हैं, ये तो आदिवासी हैं । तब सब चुप हो जाते हैं । बड़े घर की लड़की को इज्जत के लिए लड़ा जाए मैं इसको अच्छा

[श्री मनीराम बागड़ी]

मानता हूं लेकिन काश यह अच्छाई इन खानाबदोश औरों के लिए भी इस देश के लोगों में आ जाए । काश कमलापति जी त्रिपाठी जैसे महापुरुष इस तरह की घटना जब हो जाती है तो कभी उधर से उठ कर इधर आ जाएं। और चौदह आदमी मारने वाली सरकार का साथ छोड़ दें । तब देश की किस्मत बन सकती है ।

आप बड़े उछले थे जब हवाई जहाज वाली घटना का कल पता चला था किसी भी आदमी की जिन्दगी को खतरा हो तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो उसके खिलाफ आवाज उठाए । बड़े जोर से आप उछल रहे थे, नम्बर बनाने वालों में अपना नाम लिखा रहे थे लेकिन जब चौदह आदमियों को गोली से भून दिया जाता है तो आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है ।

आज देश में किस का शासन है ? क्यों गोली से उनको भूनने से आप रोक नहीं सके । बिहार की बात को ही आप लें । टाटा की कम्पनी ने दस हजार मजदूरों को जबर्दस्ती निकाल बाहर किया है । उन में से सात हजार आदिवासी हैं । ढाई हजार उन में औरतें हैं । क्यों आप टाटा के साथ बात नहीं कर सकते हैं, क्यों टाटा जैसे जालिम को गिरफ्तार नहीं करते हैं, किस में हिम्मत है जो उनके खिलाफ आवाज उठा सके ? वह आदिवासियों की जिन्दगियों के साथ खिलवाड़ करता है । बिड़ला को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं ? कौन उनको गिरफ्तार करेगा ? वह समुचय हिन्दुस्तान के जंगलों को काट कर बरबाद कर रहा है । समुचय देश में आठ घराने हैं जो हिन्दुस्तान के जंगलात के ठेकेदार बने हुए हैं । समाज के जो दुखी लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, जिनको आप उठाना चाहते हैं, वे अगर एक तिनका भी तोड़ कर ले जाते हैं तो आपकी पुलिस, आपकी फौज मिल कर कानून का सहारा ले कर उनको मारने तक तैयार हो जाती है लेकिन जो तमाम जंगलात को लूट कर खाते चले जा रहे हैं, जो इन गरीब लोगों के पेट पर ठोकर मार रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है ।

खानाबदोश लोग जो मारे-मारे फिरते हैं उनकी जिन्दगियां क्या हैं ? उनकी औरतों के साथ आज सामूहिक बलात्कार होता है, उन लोगों की जिन्दगियों को बरबाद किया जाता है। उनकी लड़कियों को बचाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। आप कहते हैं कि गुलामी की प्रथा कहां है ? लेकिन आज तक भी इस देश में गुलाम प्रथा नहीं बदली है (इंटरप्शन) कल जब हवाई जहाज में कांटा चुभ गया था तब तो आप बहुत उछल रहे थे लेकिन आज सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा फेल हो। सभी लोगों को जिन्दा रहने का अधिकार है। उन लोगों की जिन्दगियों के साथ मजाक मत करो। अगर कहीं देश में भूचाल आ गया और ये पांच करोड़ इंसान उठ गए तो इस देश को आप बचा नहीं सकेंगे, जब वे अपनी करनी पर उतर आए तो आप देश को बचा नहीं सकेंगे ।

18.41 hrs.

(MR. SPEAKER *in the Chair*)

मैं चाहूंगा कि आप फौरी तौर पर इस पर कदम उठाइए। एक तो

आप अगर कर सकते हों तो करिए कि इस किस्म के जो भी फायरिंग हों, जो भी कत्ल हों, मैं तो इसको फायरिंग नहीं कत्ल मानता हूं, अगर आप यह कहते हों कि जहां हिन्दू मुसलमान फिसाद हो वहां के एस० पी० और डी० एस० पी० को बदल दिया जाये तो जहां जिस प्रदेश में इस तरह से 14, 14 लोगों को मार दिया जाये, मैं तो कहूंगा कि कत्ल कर दिया गया हो तो कम से कम उस प्रदेश की सरकार को बदल देना चाहिए।

मैं ज्ञानी जी से कहना चाहता हूं कि अगर हिम्मत है तो जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक रेलवे के एक्सीडैंट पर इस्तीफा दे दिया था, आज इस देश के अन्दर आप पिछड़ी जाति के लोगों की आशाओं के प्रतीक हैं, इतने लोगों पर जुल्म हों, उनको गोली मार दी जाये, अच्छा मौका है, इस मौके पर आप एक नजीर-बना दीजिए, एक सिद्धांत बनाइए। मगर रास्ता आपका साफ हो गया, दिन में तो मालूम हुआ था कि इस्तीफे की बात चल गई है, गाड़ी तो चल गई है, लेकिन अब यह रुकेगी कहां पता नहीं। मेरा कहना है कि अच्छी लाइन से हो, सिद्धांत से हो।

मैं चाहूंगा कि मरने वालों को कम से कम एक लाख रुपया दिया जाये। रेप के कांड जितने हैं, जो बलात्कार के हैं, उनके केस खास अदालतों के जरिए कराये जायें और जिस लड़की के साथ बलात्कार किया गया हो, उसे कम से कम 1 लाख रुपया मिलना चाहिए जो थानों में बलात्कार होते हैं, जैसे कमला का कांड है जो बलात्कार कर के कूंए में डाल दी गई, उसके घरवालों को मुआवजा मिलना चाहिए।

जंगल के जितने ठेके हैं, चाहे बिड़ला के हों या टाटा के हों, इन सबको कैंसिल करो। यही उनकी धरती है यही उनकी कमाई है, यह उनको दो। टाटा और बिड़ला जैसे पूंजीपति लोग जो जबर्दस्ती कारखानों को बन्द कर के लोगों को निकाल रहे हैं, मैं ज्ञानी जी से पूछना चाहता हूं कि यह नजरबन्दी का कानून क्या हमारे और आपके लिए ही है, कभी टाटा और बिड़ला के भी हथकड़ी लगाओ और जेल में भेजो ताकि लोगों को पता लगे कि आपकी सरकार में कितना दम है।

आज ऐसे 10, 10 हजार आदमी बेकार हो रहे हैं और ढ़ाई-ढ़ाई हजार औरतों को मजबूर होना पड़ता है अपनी इज्जत और अस्मत बेचने के लिए। अगर आपका कोई मजबूत कदम आयेगा तो अच्छी बात होगी।

मैं आप से कहना चाहूंगा कि इसका कुछ नतीजा निकलना चाहिए वरना नतीजा तभी निकल सकता है जब इसको अमल में लायेंगे। आज हमारा समाज कुछ सड़ चुका है और हम में गन्दगी सब से ज्यादा है।

मैं देख रहा था उस दिन जब यह सवाल यहां पर उठाना था। उस दिन एक तरफ तो लाइफ इन्श्योरेंस वालों की बात थी और एक तरफ आदमी की जिन्दगी और मौत का सवाल था। हम लोग यहां बैठकर लड़ रहे थे मरने वालों के लिए और अखबारों में खबर आई एल० आई० सी० वालों की। सवाल पहले उठा मरने वालों की लेकिन वह दूसरे नम्बर पर आ रहा है। मैं एल० आई० सी० वालों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन दो हजार रुपये तनख्वाह वालों की जो परम्परा है इसको बदलो। माया बड़ी या जिन्दगी ? इन्सान की जिन्दगी जा

[श्री मनीराम बागड़ी]

रही है एक तरफ यह बात है और दूसरी तरफ करोड़ों रुपये की बात है बोलो राष्ट्र इन्सान की जिन्दगी की तरफ जाएगा या पैसे की तरफ ? अगर यह परम्परा सिर्फ पैसे की तरफ जायेगी तो इन्सान की जिन्दगी तबाह हो जायेगी।

पढ़ो गांधी जी को और डा० लोहिया को, समझो इस देश में दरिद्रनारायण को कि वह क्या कहता है । काश! यह आवाज पहले उठती।

एक माननीय सदस्य : जयप्रकाश जी की बात आप भूल गये।

श्री मनीराम बागड़ी: जयप्रकाश जी की तो सम्पूर्ण क्रांति है, वह तो आपको और हमको करनी है। उसको भी लायेंगे, समय आ रहा है।

मैं इन शब्दों के साथ आप से चाहूंगा कि आप ठंडे दिल से सोचें, समझें और विचारें और कुछ करें। कुछ और नहीं तो कम-से-कम जो सुना है कि केन्द्र का कोष होता है, प्रधान मंत्री और घर मंत्री का कोष भी होता है ।

एक माननीय सदस्य: बागड़ी जी का कोष ?

श्री मनीराम बागड़ी: मेरा कोष तो तुम्हीं हो, पता नहीं कब कंडा कटेगा । उस कोष में से आप दो। देखना, दिन बुरे आ रहे हैं, शनीचर चढ़ रहा है, जरा पुण्य करो, शायद टल जाये। अगर ऐसी जगह केन्द्रीय कोष से लोगों को पैसा मिलेगा, तो उन में विश्वास बनेगा कि केन्द्र की भी आस्था रहती है।

बात ठीक है, लेकिन कुछ फैसला करो, उस पर अमल भी करना है, मंत्री लोग अमल नहीं करते हैं। हमारे केदार पांडे जो कितने शरीफ आदमी हैं, बड़े भले आदमी हैं, लेकिन रेलवे का रिजर्वेशन दे रहे हैं कहां जाकर, गुजरात के उन लोगों को जो रिजर्वेशन के एंटी जलूस निकाल रहे थे, पांडे जी को याद ही नहीं कि गाड़ी किस को दे रहे हैं, उनको सोच समझकर काम करना चाहिए। इस से देश की सदन की मर्यादा भंग होती है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, आज हम नियम 193 के अधीन आदिवासियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं । आदिवासी सदियों से पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जिनकी संख्या इस देश में सिर्फ 5 करोड़ है । उनकी अपनी एक विशेष संस्कृति है और वे बहुत ही पिछड़े हुए हैं । सारे के सारे आदिवासी पावर्टी लाइन के नीचे रहते हैं और उन पर कई प्रकार के अत्याचार होते हैं । समाज के सब पढ़े-लिखे, पैसे वाले और जागरूक लोग आदिवासियों का शोषण करते हैं।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस ने रिजर्वेशन के बारे में कहा है । जब से हमारे देश की नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी, सत्ता में आई हैं, तब से रिजर्वेशन बढ़ा है । वह बराबर इस बात की कोशिश कर रही है कि आदिवासियों की हर तरह से तरक्की हो । लेकिन इन लोगों के शोषण को कैसे रोका जाए, अगर हम इसके बारे में राजनीति से ऊपर उठ कर चर्चा करें, तो मैं समझता हूं कि इसका कोई रास्ता निकल सकता है ।

मेरे क्षेत्र में भाभरा गांव में अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था । वह पांच हजार जन संख्या वाला गांव है और वहां पर 35 प्रतिशत लोग

आदिवासी हैं। उस गांव में बालकों और बालिकाओं के अलग अलग होस्टल हैं। वहां पर 3 और 4 मार्च के बीच की रात को एक ऐसी घटना हुई, जो इस हाउस, सारे समाज और इस देश के लोगों के लिए एक बड़ी शर्मनाक घटना है। दो बालिकाएं रात को अपने होस्टल से बाहर गईं और वापस नहीं आईं। सवेरे तलाश करने पर पता चला कि उनमें से एक बालिका का शव तीन किलोमीटर दूर बीलझर गांव के एक कुंएं में पड़ा हुआ है और दूसरी बेहोशी की हालत में रास्ते में पड़ी हुई है। इस क्षेत्र के आदिवासियों और छात्रों तथा छात्राओं में इस घटना को ले कर बहुत आक्रोष है। इस बारे में बालकों के होस्टल में रहने वाले दो लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। मगर समाज के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि उन लड़कों का इस घटना से कोई सम्बन्ध है।

उसी रात को भावुआ के डी० एस० पी०, सर्कल इन्स्पैक्टर और बहुत से जवान एक लारी और जीप ले कर पास के एक गांव में दबिश डालने गए थे। वे रात के 4 बजे आए थे और इस घटना से सम्बन्धित हैं। गांव का चौकीदार यूवैल भी इस घटना से मिला हुआ है। अभी तक उसकी टच नहीं किया गया है—उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैंने भी इस बारे में नियम 193 के अधीन एक नोटिस दिया था। मैं होम मिनिस्टर साहब से इस बारे में स्पष्ट जवाब चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी अपने क्षेत्र में लोगों और होस्टलों में रहने वाले लड़के-लड़कियों को जवाब देना पड़ता है।

जैसा कि मैंने बताया है, उस रात को 3, 4 बजे पुलिस के आदमी वहां आए और सवेरे एक बालिका की लाश तीन किलोमीटर दूर बीलझर गांव में मिली और दूसरी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई मिली, जो कि इन्दौर के एम०वाई० हास्पिटल में भर्ती है। जिस लड़की की मृत्यु हुई है, उसका नाम निर्मला था और वह 11वीं क्लास में पढ़ती थी। वह वहां के छात्र संघ की अध्यक्षा थी। एक महीना पहले जब मैं वहां पर छात्र संघ के स्नेह सम्मेलन में गया था, तो उसने मेरा स्वागत किया था। उस गांव से मेरा नज़दीक का रिश्ता है। इतनी फर्स्ट क्लास पढ़ने वाली आदिवासी लड़की थी, उस के समाज के अन्दर, उसके मां का खून खौल रहा है...

अध्यक्ष महोदय : जो एक प्वाइंट कह दिया उस से आगे बढ़िए। जिससे कि कुछ कह सकें क्योंकि टाइम बहुत कम है और बोलने वाले बहुत हैं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं।

दूसरी लड़की वसंती, अभी वह वहां इंदौर अस्पताल में भर्ती है। पूरी तरह से वह बीमार है। उस को चलाया नहीं जा सकता, वह उठ नहीं सकती और वह पुलिस की कस्टडी में रखी हुई है। मैं भी दो बार उस लड़की से मिलने गया। पहली बार मिला तब भी पुलिस की कस्टडी में थी और दूसरी बार मिला तो भी पुलिस की कस्टडी में थी। पुलिस ने मेरे खिलाफ भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई 13 अप्रेल को कि यह भूरिया जी संसद सदस्य आते हैं और बार बार जांच बदलवाने की कोशिश करते हैं। इस से साफ शंका होती है कि इस में पुलिस इन्वाल्वड है। मैं मंत्री जी से यह चाहता हूं कि सी० बी० आई० के द्वारा इस की इन्क्वायरी कराएं और इस घटना की पूरी तरह से जांच कराएं। आदिवासी एरियाज में ऐसे अधिकारियों को तनात किया जाय जो असल में आदिवासियों के प्रति हमदर्दी रखते हैं, सेवा करना

[श्री दलीप सिंह भूरिया]

चाहते हैं, ऐसे अधिकारी को वहां रखा जाय। जहां ऐसी घटनाएं घटती हैं वहां के अधिकारियों को तुरन्त हटाया जाना चाहिए, उनको वहां नहीं रखना चाहिए। अभी भी वह पुलिस अधीक्षक जिस ने केस बनाया उसी स्टेशन पर झाबुआ में मौजूद है। ऐसे अधिकारियों को तुरन्त निलम्बित कर के वहां से हटाया जाना चाहिए। इस की सी० बी० आई० से जांच कराना आवश्यक है।

दूसरे, मैं यह कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के बारे में बहुत सारी बातें होती रहती हैं। अभी मैं ने बस्तर के मामले में 377 उठाया। क्या हो रहा है हमारे देश के अन्दर ? जो उनकी संस्कृति है, जो उन का इतिहास है। दूसरी जगह ले जा कर उसको छपाया जा रहा है, लन्दन में छपाया जा रहा है, कौन रोकेगा इस को ? यह हमारे लिए बड़ा विचारणीय प्रश्न है। अगर इस को सख्ती से नहीं दबाया गया तो जो पांच करोड़ आदिवासी लोग हैं वह आज इस बात के लिए तयार नहीं हैं। उनके अन्दर आक्रोश है, उन में संघर्ष करने की भावना है। मैं चाहता हू कि सरकार और हमारे माननीय होम मिनिस्टर इस के बारे में जितना ज्यादा हो सकता है उतनी ज्यादा कार्यवाही करें और जहां तक झाबुआ की बात है मैं विशेष कर मंत्री जी से कहूंगा कि इस के अन्दर सी० बी० आई० की जांच कराएं और जो असलियत है, उसकी रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत करें। यही मैं चाहता हूं। आप ने समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

SHRI G. NARSIMHA REDDY (Adilabad): Mr. Speaker, I am very thankful to our friend Shri Fernandes who has raised this important discussion in this House. I am further thankful to him because he requested us to raise above the party level so that we may be able to help the Government in protecting the Scheduled Tribes of the country.

. . . . . .

I represent Adilabad (Andhra) Parliamentary Constituency. I would like to give a little background of the situation that has led to firing. We all know that the entire tribal Population of our country, unfortunately, from thousands of years had been leading aloof and secluded life from the mainstream of this country. Our national leaders after independence have rightly come to a conclusion and decided that a separate protection or safety should be given to the Scheduled Tribes so that they may be able to come at par with other people of this nation. So, keeping that in view it is a very funny co-incidence that the Government of India on 28th April 1960 that is exactly 21 years from now appointed U.N. Dhebar Committee to go into the details of the tribal communities in this country. The Committee submitted the report indicating in what way we will be able to help them. I quote the observation of the Committee:

> "The problem of problems is not to disturb the harmony of tribal life and simultaneously work for the advance, not to impose anything upon the tribals and simultaneously work for their integration as members and part of the Indian family. That is the mission assigned by the father of the Nation."

19 hrs.

I am only trying to give this background because, with this background, with this conceived idea of our national leaders, the Commission has submitted its report. The Commission in its report has further observed that the tribal population till then, that is, before what happened in 1960, were

occupying agricultural land, doing agriculture, that is, *podu* type of agriculture. Whenever non-tribals enter a village inhabited by the tribals, the sentiments of the tribals are that they will not like to stay in the village with other communities. Whenever non-tribals enter into a tribal village, the tribals will start vacating it and they will go on the hill-tops and enter into the interior of forests. It is only for this reason that the Commission has rightly observed that these tribal communities of our nation should be protected and that we should not allow any non-tribal to encroach upon their land. Keeping this in view, the Andhra Pradesh Government has passed certain rules.

If we go back to our history, the Gonds are the largest tribal group in India and these Gonds are mostly in Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa and Maharashtra. Once upon a time, there was a kingdom of Gonds called Gondwana. They are now distributed in the districts of Chhindwara, Mandla, Chanda, Adilabad and Warrangal. These districts were once upon a time ruled by the kingdom of Gonds. They enjoyed complete independence and they used to have, once a year, a *darbar* in Kaslapur, that is, in Adilabad district of Andhra Pradesh which is hardly 15 miles away from Indravalli where this unfortunate incident took place.

After Independence, our Congress Government which took over the State Government of Andhra Pradesh, to keep up the sentiments of tribals in that area, followed the same system of holding a *darbar* every year in Keslapur. There is a temple. Every year, a date is fixed. The Collector is the President of the Committee. All the tribal MLAs and tribal Chief of that area are members of it and, with their consultation a darbar is convened. So, every year, almost all the Gonds come there and discuss about their problems and the Collector tries to solve them. In this way, even today, it is continuing. As far as possible, even the Tribal Welfare Minister also used to attend.

As we all know, the tribals are mainly dependent on land and forest. Their home is not a hut. I would like to remind the hon. Members that they feel at home if they are in a forest area. This has been going on for the last so many ages. Keeping all this in view, the previous Governments of Andhra Pradesh have taken sufficient care to protect the tribals in their own homeland.

I would like to mention here that according to the past history also, there were some occasions, whenever the previous Governments or non-non-tribal people encroached upon the rights of tribals or tried to snatch away the land which they were ploughing, they had revolted. A good number of times, there were such occasions. I would like to cite one or two examples. In the Agency area of Andhra Pradesh, there were revolts by the Koyas. The last of these revolts against the oppression of the then petty officials was led by Alluri Sitharam Raju who himself was a tribal. This synchronised with the non-cooperation movement launched by our Congress Party.

10.05 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

In comparatively recent times also, in Adilabad district of Andhra Pradesh, many Gonds and Kolams rebelled in 1941 as a result of alienation of their land from tribals to non-tribals. I am only trying to give you the back ground of the tribals since last one year. Now, the present Government, as I said earlier, keeping all this in view, tried to protect their interests by passing different laws. They have first declared certain areas as scheduled areas. There no non-tribal can possess any agricultural land. In the Constitution of India, a provision was made and State Governments were

[Shri G. Narsimha Reddy]

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

empowered to take up legislation and to get them employed in industries and to protect them from money-lenders who were exploiting them.

These were some of the measures of the State Government to protect the tribals from exploitation. I will quote the Andhra Pradesh legislation.

(1) The Scheduled Areas Estate (Reduction of Rent) Regulation 1951;

(2) Madras Scheduled Areas Estates (Abolition and Conversion into Ryiwari) Regulation, 1951;

(3) A. P. Scheduled Areas Land Transfer Regulation 1959.

In our Andhra Pradesh particularly this area belongs to the erstwhile Hyderabad State and, earlier from 1917 onwards the British Government also realised the situation of the tribals in our area. From that time onwards a regular legislation was passed for protecting the tribal land. That is, by not permitting non-tribals to enter into or encroaching into their area.

But in spite of all this legislation in their favour, what is the position today? As I have said earlier, the Dhebar Committee has submitted its report almost 21 years ago. If we review what had happened in these 21 years, we can know whether we successfully protected their interests. My personal opinion is that our efforts were sincere and genuine but, I am very sorry to say, that we have failed in protecting their interests, specially in land.

I will give you the example of Utnur taluk which was entirely declared as an agency area. In spite of that, today the situation is unsatisfactory. As you might have known from the press reports, today the population if Indervelly is 6,000 non-tribals. Hardly 2 or 3 per cent of tribals are there. The tribal population was very much less even in 1947 when their number was only 9 in Indervelly. Similarly, even when the Utnur was the Headquarters of Utnur taluk, then also 95 per cent of the population were non-tribals. Today the tribal population of Utnur is hardly 4 per cent. So, 95 per cent are non-tribals. (*Interruptions*).

I am only trying to impress that within 21 years, we could not successfully protect the interests of tribals. We could not even stop the encroachments from the non-tribals. Apart from that, when we talk about exploitation, we must also bear or keep one thing in mind. What our State Governments are doing?

If you ask my sincere opinion, I must say that unfortunately there are some exploiters of the tribals who are operating without the knowledge of the State Government. I would like to cite the instance of the Girijan Corporation in our State. This Corporation is meant to protect the tribals from the money-lenders. They have to meet all the requirements of the tribals including purchasing of the produce which they bring from the land. For example, gum purchase in our district is a monopoly of the Girijan Corporation.

For the last so many years, the Girijan Corporation had been purchasing gum at a very low rate. Now, the other merchants, though they are not supposed to purchase—because it is the monopoly of the Girijan Corporation—have been purchasing paying a high rate and are smuggling it to different places—Bombay and other places. I would only like to bring to your notice that whenever I raised the issue with the Girijan Corporation, they would tell me that, if they purchased at a high rate, they would run in losses. So, we have to apply our mind to this. Are we maintaining the Girijan Corporation or other Societies to protect the tribals or are they run for their profits exploiting the tribals?

Similarly, in Madhya Pradesh; I would like to quote here Madhya

Pradesh: in Madhya Pradesh, as you know, the collection of beedi leaves in done mostly by the tribals and the rural labourers. Last year, in 1980, what happened? Out of 1800 units in Madhya Pradesh, almost 1000 units, for some reason or the other, were given to the Marketing Federation and for departmental collection.

They had collected only 50 per cent of the normal collection. The result is that the rural labourers and the tribals who are there to collect the beddi leaves were deprived of their wages; as per our rough calculation, the loss of wages was Rs. 3 to 3-1/2 crores in that year. As short collection took place, the beedi leaves became short in this country. So, the beedi manufacturers, that is, the labourers who actually use the beedi leaves as the raw material and manufacture lost about Rs. 10 crores by way of wages. This is not an easy joke. This is a very serious matter where we are indirectly depriving the rights of the tribals and agricultural labourers.

Coming to the third point, in Maharashtra also there is the Abujmadia area which is mainly in Madhya Pradesh but a little portion of which comes in Maharashtra. There, the tribals are in a very primitive stage....

AN HON MEMBER: Madiars.

SHRI G. NARSIMHA REDDY: Even today they do podu cultivation, in the sense that each family has only 50 acres and in the 12-year term, every year in about three acres they do agriculture. Those tribals have met and complained to me that the State Government wants them to vacate the land or wants them to stop felling the trees for podu cultivation. In this way, directly, when they are exploiting the tribals, a situation has come when the entire Gundwana area...

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI G. NARSIMHA REDDY: I hardly speak, Sir. If I do not make points, you can ask me to sit down. I have not come to my point, to Adilabad.

MR. CHAIRMAN: If you begin from Kanya Kumari, you will come to Adilabad only at 8.00 p.m....

SHRI G. NARSIMHA REDDY: I will finish. I have taken only five minutes.

MR. CHAIRMAN: You have taken 15 minutes.

SHRI G. NARSIMHA REDDY: Now I will come to Adilabad. Regarding the Adilabad situation, Mr. Fernandes has spoken. Here I would like to say that the non-tribals, continuously since the last 20 years, have been occupying the lands of tribals. Today the tribals have been shifted to the hilly areas in which there is no dispute; it has become a universal truth. But to say that the police has killed the tribals may not be very justifiable even for Mr. Fernandes to say. There I would like to say that the CPML, which they call as a War Group, have been organizing for the last five to six years in different manners; on that particular.... (*Interruptions*),

श्री मनीराम बागड़ी : सामने मारना हो तो नक्सलाइट कह दो। यह मन्त्र पढ़ो और आदमी को मार दो, कोई पाप नहीं लगेगा।

SHRI G. NARSIMHA REDDY: I will come to that. It is a very unfortunate incident for which we are all ashamed. I do not justify the firing. It is very unfortunate. The situation which was there was tense. Since the last 5 to 6 months the tribals were feeling agitated. Our District Collector, Mr. Srinivasan who is one of the most efficient officers we have, went there and collected 4000 to 5000 tribals five months back. He took all his district officers and consulted them and took down all their grievances. From that time onwards they had been on tours and were trying to solve the problem. The CPM(L) knew very well the action of the State Government through the Collector and the way they are moving because he has taken it up as an individual challenge that he

[Shri G. Narsimha Reddy]

will satisfy the tribals and he will do justice to the tribals. So when he continued, the CPML felt probably that this way they may lose the sympathy of the tribals because the benefits are being received by the tribals. At that moment they wanted to call a meeting and they announced that they would distribute the land which they have lost. When the meeting was conducted, about 10000 to 15000 people tried to collect. They were all non-tribals. There was a committee of non-tribals. The entire Indravalli village is full of non-tribals. For their protection they thought that they should convene a meeting in the same village. The SP and DSP went round the village and told the tribals 'You please don't come for this meeting because we have imposed Section 144.' When the villagers from the morning onwards went on collecting around the area, it is wrong to say for Mr. Fernandes that the authorities asked them not to conduct the meeting. The RDO in charge or the Collector clearly told them to conduct the meeting but conduct it outside the Panchayat boundary. There was nothing wrong and he askesd them to conduct the meeting outside. But, unfortunately, at the instigation of some anti-social elements they rushed....

MR. CHAIRMAN: He is not in a position to conclude.

SHRI G. NARSIMHA REDDY: I have not come to that point. I am trying to say that it is wrong to say that nobody allowed them to conduct the meeting. I repeatedly say that because Indravali consists of only non-tribals—there are no tribals in that village—therefore the possibility of heart burning between tribals and non-tribals which is simmering for so many years, when the tribals conducted a meeting while the non-tribals also wanted to conduct a meeting in their own village, it is but natural that a clash would take place and it will lead to a chaotic situation. .... (*Interruptions*). Only when they attacked and rushed in, this thing happened. This is the eye-witness information of the local MLA. Sir, we are all discussing this matter above political level. It is a fact that these people when they came at 5 O'clock, the trouble started. One Police constable was hit by stones and he ran away for 2 furlongs and when the stone hit the SP, luckily he was wearing a helmet and so his life was saved. It was at that moment that these people opened fire.

श्री मनीराम बागड़ी : यह किसकी वकालत कर रहे हो। क्या फालतू बातें कर रहे हैं ? ..(व्यवधान)..

SHRI G. NARSIMHA REDDY: Our ment saying that he would ment saying that he would like to regroup our Gond colony, the tribal colony. So, in this way when we talk about the tribals' welfare we have to keep in our mind.....

(*Interruptions*)

श्री मनीराम बागड़ी : आप इन लोगों के कत्ल को जस्टीफाई कर रहे हैं। क्या फालतू बातें कर रहे हो।... (व्यवधान) कितने लोगों को गोली से मारते रहोगे।... (व्यवधान)... आप पुलिस वालों की वकालत कर रहे हो।

आचार्य भगवान देव : (अजमेर) : पुलिस वाले क्या आदमी नहीं हैं।

SHRI G. NARSIMHA REDDY: I am not justifying the firing. I belong to that constituency. I personally went round. I was Chairman of Zila Parishad before coming to Lok Sabha. I know many persons and the places. I talked to the tribals. I know the problem of the place. I know some people have died also. It is more painful to me than any Member who is sitting here.

Sir, I am only trying to narrate the stories because I cannot come to any conclusion. It is for the House, it is for the nation and it is for the people to come to the conclusion. I am only trying to say that time has now come

when Government of India has to think twice whether we have to set up another commission. You think over the main problems as to whther we have done anything in these twenty one years. For that what we have to do is how we want to protect the tribals and to win them over.

With these words, I thank you, Mr. Chairman, for the time which you have given me.

MR. CHAIRMAN: Shri Balanandan.

SHRI E. BALANANDAN (Mukundapuram): Mr. Chairman, we are discussing the problem and, as the previous speaker said, this should be discussed above party level. Everybody would like to have a discussion like this. The point came up for discussion because of the horrible Iravalli incident as was properly narrated by my friend, Shri George Fernandes. I may also add some points to it.

The police completely mishandled the situation and they have killed fourteen people by point blank firings as everybody said here. The Girijan Rati Coali Songam announced a public meeting. On the same day, at the very same place, the non-adivasi people also wanted to have a public meeting. Normally everybody would expect that the police would have asked the non-adivasi people to have their meeting next day or it might be held somewhere else. Instead, what the police did was that they had banned the two meetings. That is the version of the Home Minister. The Home Minister of Andhra Pradesh declared in the Assembly itself. Having banned the meetings, what was the arrangement made by the police? They wanted to protect the non-adivasis. An alibi was taken that the meeting was banned just to attack the adivasis. If you read the paper report and the statemnt made by the Home Minister in the Assembly, nobody will have any doubt about this.

The explanation given by the Home Minister in the Assembly itself had admitted that there were two mistakes—firstly there was no proper police intelligence report; secondly, there was not sufficient police force in the district. The other statement my friend was making was that the district collector was active etc., etc. This incident did not take place all of a sudden; there was an agitation going on for months about the agricultural wages etc. and these people wanted to organise a public meeting. *The agitated adivasis—the agricultural* workers' union—legally wanted to have a public meeting. In that very place, others also wanted to have a public meeting on the same day. Normally, any police officer handling the situation, might ask this party or that party to have the meeting somewhere else to avoid tension. The tension was there for long. The Home Minister of Andhra Pradesh declared in the Assmbly itself that there was not sufficient police and there was no proper intelligence report. Therefore, what happened was that these people a fourteen of them—were killed by the police like the hunters shooting the birds. Many others were also injured. This was the situation there. Everybody should be sorry for that. My friends on the other side wanted that instead of a magisterial enquiry, some judicial enquiry should be there. I support their demand. But that alone will not be sufficient. If anybody goes deep into the question then he will come to know what is the real problem over there. Sir, in 1959 in Andhra Pradesh Scheduled Area Land Transfer Regulation Act was passed. Under this Act in this particular area the land should be held only by Adivasis. Now, what happened. This Act had been enforced in this area in 1968. After so many years what we find is that there is no land in the hands of the Adivasis there and the record shows that 1,500 cases are pending in the courts. That means practically the land of the Adivasis has been taken away by others. Even

[Shri E. Balanandan]

after 20 years of passing the Act and 10 years of its enforcement the land is not in the hands of the Adivasis. This is the main issue for which a remedy has to be found out.

Now, Sir, I would like to quote from the *Indian Express* Editorial dated 25th April, 1981:

> "It is foolish to look at this problem purely in terms of law and order issue. Adivasis have legitimate grievences in that they have been denied access to the agricultural land which traditionally belonged to them."

The land which traditionally belonged to them has been taken away. That was the issue on which, these people were agitating. So, the problem of Advasis has to be viewed and solution sought on the socio-economic base.

Sir, here in this August House and everywhere else the ruling party members daily talk of Harijans, Girijans, Tribals, etc. What is their plight? I am not going into the details of Andhra issue about which the previous speakers have already spoken at length. Now, what is the position of these people in other areas as well? Sir, if you go through the daily newspapers you will find shocking reports about attacks on Harijans, Girijans and Adivasis. I may only narrate two or three small examples. If we go through the news all of us will be ashamed of it. In Orissa Assembly the Orissa Revenue Minister said that he would take up the point with the Government of India on the discrimination shown to Adivasis. There are some Bengali settlers in Danda Karanya and they are being given Rs. 3,000 for housing and Rs. 700 for buying a pair of bullocks whereas the Adivasis are given only Rs. 1,000/- for housing and Rs. 600/- for buying a pair of bullocks. Why? Now, the Revenue Minister of Orissa said that he was going to take up this matter with the Central Government. Sir, the Central leaders day in and day out talk about helping the Adivasis and giving them weightage over others but is it the type of weightage which is given? While others are given Rs. 3,000/- for housing these people are given only Rs. 1,000/-. I can understand that some may think that the Adivasis need not be given Rs. 3,000/- as they need not live in better houses but, for buying bullocks can Advasis buy a pair of bullocks for Rs. 100/- less than others?

Another point is that some report has come from Bihar. A Memorandum was submitted to the Government by one Miss Laru Janko, a Mahila Samithi Leader, and Mr. Purnendu Mazumdar, General Secretary, United Mineral Workers' Union. He has brought out the situation in that Memorandum very clearly. In Chota Nagpur district these Adivasis are brought by agents saying that they will be given work there in brick-making; they are brought in saying that they will be employed in brick kilns and so on. But what do they do, Sir? You will be really shocked to know this. I am unable to say it in Parliament. They rape these birls. These girls are being manhandled and beaten up. They are not allowed to go back to their places, if they want to go back. This is what is being done. This is the sort of thing which is happening in this area. This sort of treatment is being given to these women in Chota Nagpur area.

MR. CHAIRMAN: You may please conclude.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgragur): Sir, the time is not enough. You may kindly extend the time.

SHRI E. BALANANDAN: There is one Newspaper Report which I want to refer to. This is a Report from *Deccan Herald* and the date is 8th April 1981. The Heading is:

> "Kolhanese 'declare' independence."

I would like to quote only one para from this report. It says :

"Thousands of tribals in Kolhan in Singhbhum District were told at a meeting at Chaibasa last week that the Government of free India had no right to rule their territory, which had been administered under the Wilkinson's Rule of the Bengal Regulation XIII of 1833."

MR. CHAIRMAN: How does it help you in this case?

SHRI E. BALANANDAN: I shall come to that. These people declared independence and wrote to the British Secretary saying that they are an independent State. Now my point is, why are these Adivasis being subjected to this kind of temptation? For the last 33 years or 32 years, we were unable to do anything to them. These elements go on exploiting the Adivasis, they create dissension among them, and they try to destabilise the country. But since I have not got the time now, I do not want to go into it in detail. Now, Sir, I do feel that if we do not take proper steps and remedies to help these Adivasis, I am afraid, this problem cannot be solved. If you want to solve this problem you should give them land. The foremost and the single most important step that is necessary here is to give them land. You should give them land to live; you should help them in all ways; you should give them the wherewithal for cultivating the land. There should be arrangements made for financial help for them. The State should help them in every possible way to improve their social and economic condition, keeping the environment as it is, without disturbing the same. There should be proper efforts made to educate them. This is very necessary. All these efforts, if they are properly undertaken, will bring them into the mainstream of the life of the people of the country. By this way only we can solve this problem of the Adivasis. With these words I conclude.

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY (Amalapuram): Sir, the problem of the atrocities on Adivasis must be viewed as a general phenomenon. The names which we frequently hear are like Belchi, Narainpur, Pipra, Parasbigha, Gua, and now Indervalli—are not just names of places nor even isolated incidents. They are the symbol of the condition of the suppressed people of this country. These people have been systematically suppressed. We can understand their basic problem if you look at it separately, which is different from others. The reason for the atrocities on tribal people are different from the reason for the artrocities on the Scheduled Castes. The Scheduled Tribes suffer from acute poverty and therefore, the economic backwardness is the reason for their cry for justice whereas the Scheduled Castes suffer from inequality in social status along with economic backwardness. Therefore, a Committee called Dhebar Committee which was appointed to go into various problems had made it very clear that the problem of the Tribals related to the main source of their livelihood, that is, agriculture and the forest produce. But actually, though there are statutory provisions and recommendations and also many laws enacted in this regard, there is a systematic massive deforestation going on, with the result they are losing their land and are shunted to interior parts of the country. This has resulted in a kind of agitation amongst them and they showed resentment. Whenever there is resentment in them, it is systematically suppressed. We are aware that 80 per cent of them are illiterates and 90 per cent of them continue to eke out a miserable living from agriculture. When ever there are attempts to make any improvement on their lands, they never object to that. Their only grievance is that there should be an equitable distribution of the fruits of the various land development plans. The development of the tribal areas is also linked with the industrialisation of the country as a whole. It is because of easy availability of minerals be it coal, iron, manganese, asbestos, mica, Chinaclay and copper. There is so much of availability of mineral resources in those areas.

[Shri Kusuma Krishna Murthy]

Whenever the tribal people are living, most of them are living in isolated places situated in forest and in hills. Whenever industrialisation takes place in those places where there is a plenty of mineral resources, outsiders would come there and engage themselves in the developmental schemes and reap the benefits of the development. But unfortunately the Tribal people have not been given any employment opportunity in the industrialisation of the tribal areas. They are exploited. Outsiders would take the lion's share and the tribals are given a very very meagre share. Mr. George Fernandes was talking about their employment position. He is correct in his statement. He has expressed that there is a lot of resentment and unhappiness among the tribal people. When he was the Industries Minister, I raised this issue. He was perfectly correct in saying that the representation of these people in any public sector undertakings or any nationalised banks or any other place of works is quite insignificant. In reply to my Starred Question No. 41 dated July 19, 1978 about statutory measures to provide gainful employment to Scheduled Tribes and Scheduled Castes in the institutions and organisations which derive financial assistance from Government nationalised banks, Mr. Fernandes the then Industries Minister, felt that statutory or other measures for this purpose would not be appropriate. It was said that the trade organisation might be persuaded to take steps to ensure that an adequate share of employment was given to the scheduled castes and scheduled tribes. He had expressed a lot of sympathy for them, but when I asked for a small thing when he was incharge of a Ministry which was capable of providing gainful employment, he was trying to evade. Our impression is that those who express their concern for the problems of the scheduled castes and scheduled tribes if they are given the responsibility to implement measures for their well-being, they shirk the responsibility.

A number of hon. Members have expresed their concern about the non-implementation of laws to solve the problems of these people. For example, there are provisions, statutory laws as also enactments to protect the forests, but we have not been able to stop deforestation. Therefore, their problems remain as they were and these people have started receding to the interior parts.

Coming to the incident at Indervalli, it is another clear case of exploitation, exploitation in a different sense. The tribals are basically innocent people, as our friend said. The Gonds are basically peace-loving and law-abiding tribe. But their innocence, helplessness and illiteracy has been exploited by some of the undesirable elements for their party purposes. When I talked to one of the representatives of the tribals there, he made it very clear that party considerations were very much there in this episode. It was not a fight between the tribals and the Government; it was a fight between the Government and the extremists. Apart from this, some people said that the Government did not make any efforts to avert this incident. Before this unfortunate incident, they made some arrests. Of course, nobody will support this kind of incident of killings. But there are evidences that the police also exercised considerable restraint on a few earlier occasions, but if you go into these things and analyse these, they wanted to prove that the Government was quite ineffective in handling these things, and they wanted to prove that there was no Government at all. This was because on earlier occasions the police exercised considerable restraint to avoid casualties. Taking advantage of that, the innocent tribes were instigated and encouraged by the extremists and this unfortunate incident consequently took place. We do not support that unfortunate killings at all. Government should have taken all precautions.

The problem of tribals can only be solved, when their mainstay of life,

forests and forest produce, is properly protected. When I went to Orissa and had discussions with some representatives of the tribals, they said that some of the Corporations meant to safeguard their interests were not able to do so properly. The funds provided to these Corporations were not adequate. When they go to the market to purchase the forest produce of the tribals, they are not abe to purchase the total quantity; they are able to purchase only 25 or 30 per cent of the total produce. Consequently, the middlemen are exploiting the situation. The money-lenders and the contractors in connivance with the Forest Department are coming in their way of development.

The Government should appoint a Committee to go into these matters again and find out the loopholes and take corrective measures to see that all the measures already decided upon to protect their interests are properly implemented. Particularly, the forests and their lands should be protected and they should be given proper remuneration for their forest produce. Only then, their problems would be solved. Apart from this the Government should make a systematic effort to see that they are brought to the mainstream of national life; they should not be treated just like a show piece in a show case, because we say frequently that we want to protect and keep their culture intact. Just because we want to keep their culture and heritage intact, we should not continue to keep them in the forests. That would not be correct. While we must retain their culture, we must see that they are brought to the mainstream of national life.

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : सभापति महोदय, जार्ज साहब ने इस बहस को शुरू करने से पहले कहा था कि हम लोगों को सियासत से ऊपर उठना चाहिए और सियासत से ऊपर उठ कर इन मामलों पर गौर करना चाहिए जो मुल्क में हो रहे हैं और अक्सर हो रहे हैं। उधर के लोगों ने भी यह बात कही लेकिन बदकिस्मती यह है कि यह बात कहने के बावजूद वह पार्टी पालिटिक्स को सामने लाए और वही जो एक तरीका है प्रोपेगैंडा का वही स्टार्ट किया। बिला जरूरत मोहतरिम प्राइम मिनिस्टर का नाम लाया गया और यह दिखाने की कोशिश की गई कि ट्राइबल्स के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। इस में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो आंकड़े जार्ज साहब ने दिए हैं वह खुद इस बात के सबूत हैं कि क्या हमारी सरकार ने पिछले तीस सालों में किया है और क्या करने की जरूरत थी। मुझे एक शेर याद आ रहा है, हमारी गवर्नमेंट तो बिल्कुल उस के मुताबिक हो गई है और उस के मुताबिक अमल कर रही है —

गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बन्द हैं।

रोइए जार जार क्यों कीजिए हाय हाय क्यों ।।

ये सोचते हैं कि लोगों को तो इस मुल्क में मरना ही है, रोजाना, जिन लोगों पर बार बार गोलियां चलती हैं, जिनकी मौत होती है उन के बारे में यहां चर्चा क्यों की जाती है? इस तरीके का ऐटीच्यूड हमारे कुछ साथियों ने यहां दिखाने की कोशिश की है।

हमें देखना पड़ेगा कि ट्राइबल्स को आखिर क्या शिकायतें हैं जिन को दूर करने में हम नाकाम रहे हैं। अगर आप इस की तवारीख देखें तो बस्तर के जो राजा थे प्रवीन चन्द्र भंज देव, उन के महल के अन्दर जा कर पुलिस ने फ़ायरिंग की थी और उस वक्त भी यही बात कही थी कि ट्राइबल्स वहां पर पुलिस के ऊपर हमला करने के लिए तैयारी कर रहे थे और जहां पर भी यह वाकया हुआ है, ट्राइबल्स के ऊपर ज्यादती और जुल्म हुआ है वहां पुलिस ने हमेशा यही कहा है कि पुलिस के

[श्री रशीद मसूद]

ऊपर हमला करने की तैयारी ट्राइबल्स कर रहे थे।

इस घटना में वहां क्या हुआ था ? ट्राइबल्स चाहते यह हैं कि उन की तहजीब और तमद्दुन बरकरार रहे। लेकिन तहजीब और तमद्दुन तब बरकरार रह सकता है कि जब उन के अन्दर दूसरे इण्टरफेयरेंस न करें। जैसा कि मेरे काबिल दोस्त, माननीय सदस्य ने बताया इन्द्रावल्ली में भी अब से दस बारह साल पहले काफी ज्यादा लगभग 80 फीसदी तादाद ट्राइबल्स की थी लेकिन आज वहां दो तीन फीसदी ट्राइबल्स की तादाद रह गई। ऐसी सूरत में उन को अपनी पूरी तहजीब के खत्म होने का एहसास होता है और उसको प्रिजर्व करने के लिए उन को लड़ने की जरूरत पेश आती है या उस में पीसफुल मीन्स से कुछ करने की हालत पेश आती है। मैं अपने दोस्त से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं जो उन्होंने फरमाया कि ट्राइबल्स को मना किया था, 144 लागू था और उनको कहा कि कहीं और जा कर सभा कर लीजिए। बल्कि असल बात यह है कि जो लैंडलार्ड्स हैं और वह वही लैंडलार्ड्स हैं जिन्होंने इन ट्राइबल्स की जमीन को छीन कर अपने कब्जे में कर लिया है, और उन को भिखारी बना दिया है उनको जब पुलिस से मिल कर इजाजत दे दी गई अपनी मीटिंग करने की तो उन्होंने पुलिस से मिल कर दूसरी मीटिंग अपनी वहां पर अरेंज की, इस का बहाना बना कर उस मीटिंग को कैंसिल करने की बात बिल्कुल आखिर में की और नतीजा यह हुआ, कोई भी अगर उस सूरत में होता, ट्राइबल्स ही क्या अगर मैं या कोई और भी पोलिटिकल पार्टी होती या कोई कम्यूनिटी होती चाहे कितनी ही कमजोर वह क्यों न होती अगर उस को इस तरह से सप्रेस करने की बात की जाती तो वह जरूर ऐसा कहती कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और वहीं उन्होंने कहा कि हम तो करेंगे जलसा क्योंकि हमारा पहले से तय था और जब उन्होंने पीसफुल मीटिंग की तो उन के ऊपर गोली चला दी। फिर वही स्टोरी बयान कर दी गई कि वह तो उन्होंने पुलिस पर हमला किया था।

मुझे याद आ रहा है, शायद जार्ज साहब को भी याद होगा, सन् 1974 में शहादा में एक बहुत बड़ी मीटिंग की गई थी लैंडलार्ड्स की तरफ से और उस के अन्दर यह तय किया गया जिस में एक शूगर फैक्ट्री के मालिक जो इत्तफाक से रूलिंग पार्टी के मेम्बर हैं उन्होंने यह कहा कि हमें 25 लाख रुपया इकट्ठा करना चाहिए और इन ट्राइबल्स से जो हमारे खेत काट लेते हैं और जो हमारी जमीनों पर, हालांकि वह जमीन ग्राम समाज की थी, अपने जानवर चराते हैं, इनसे बचने का कोई उपाय करना चाहिए। इस के लिए हर गांव में दो दो तीन तीन आदमी रखने चाहिएं फौजी और उन्होंने राजस्थान से दूसरी जगहों से लोध और पठान बुला लिए। वह दो दो तीन तीन हर गांव में छोड़े गए। इस के बाद एमर्जेंसी का जमाना आ गया। इस एमर्जेंसी के जमाने में इन्हीं लोगों ने उन की औरतें सब उठा लीं। इत्तफाक की बात कि 77 का जमाना आया और उस से निजात मिली.. (व्यवधान) .. यह रिकार्ड पर है, यह कोई अपनी बात मैं नहीं कह रहा हूं।

अब की मर्त्तबा क्या हुआ 14 जनवरी को ? इस साल उन्होंने कहा कि अब की मर्त्तबा हमें पूरी फौज इकट्ठी करनी चाहिए 500 आदमियों की फिर एक साथ मुकाबिला किया जाये एक एक गांव में जा कर। नतीजा यह हुआ कि शहादा से कुछ 6 मील दूर फिर दोबारा 14 जनवरी को गोली चली और 4 ट्राइबल्स जख्मी हुए।

फिर वही रिपोर्ट आई। पुलिस से मिल गए बड़े बड़े लैंडलार्ड्स और रिपोर्ट यह आई कि इन्होंने पुलिस पर हमला किया था, लिहाज़ा हमें अपने डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। और राम स्वरूप सिंह, महाराष्ट्र के मिनिस्टर, जोकि इंक्वायरी पर गए उन्होंने 16 तारीख को असेम्बली में बयान दिया कि ट्राइबल्स की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी, पुलिस ने बिला वजह गोली चलाई,। तो यह पोज़ीशन है। और सिर्फ यही मामला नहीं है, हर मामले में ऐसा हीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि पार्टी पालिटिक्स से ऊपर उठें लेकिन और लोग नहीं चाहते हैं। अभी ओखला की लड़की का ही मामला चल रहा था, उसको उठा लिया गया। हमारे एक मिनिस्टर साहब ने, जब उनसे कांग्रेस (आई) के लोग मिलने के लिए गए और कहा कि इसमें कांग्रेस (आई) के लोग भी शामिल हैं, तो उनसे उन्होंने कहा कि इसमें मिसेज़ दण्डवते और सिकन्दर बख्त भी आ गए हैं इसलिए यह पार्टी पालिटिक्स चल रही है। ... (व्यवधान) ..

अभी तो 8 मिनट पूरे नहीं हुए हैं। मैं खत्म कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह था कि यह प्राब्लम बहुत सीरियस है। इस मामले में ज़बानी ही नहीं, प्रैक्टिकल तरीके से हमको पार्टी पालिटिक्स से ऊपर उठना चाहिए। हमारे ट्राइबल्स अपनी तहज़ीब और तमद्दन बरकरार रखना चाहते हैं। त्रिपुरा का ही मसला है जहां 1971 में 4 लाख की आबादी में 3 लाख ट्राइबल्स थे और आज 17 लाख की आबादी में 4 लाख ट्राइबल्स हैं। हर जगह ऐसा हो रहा है। इसको रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। और इन्द्रावली का जो मसला है उसकी हाईकोर्ट जज के ज़रिए से जुडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सही फैक्ट्स सामने आ सकें और जो लोग ज़िम्मेदार पाये जायें उनको सख्त सज़ा दी जाये। दूसरे, लोकल लेबिल पर कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें ट्राइबल्स का ज्यादातर रिप्रेजेन्टेशन हो, जो कि उनकी ग्रीवान्सेज़ को दूर कर सके।

मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[شری رشید مسعود (سہارنپور) :

سبھاپتی مہودے - جارج صاحب نے اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو سیاست سے اوپر اٹھنا چاہئے اور سیاست سے اوپر اٹھ کر ان معاملوں پر غور کرنا چاہئے جو ملک میں ہو رہے ہیں اور اکثر ہو رہے ہیں - ادھر کے لوگوں نے بھی یہ بات کہی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بات کہنے کے باوجود وہ پارٹی پالیٹکس کو سامنے لائے اور وہی جو ایک طریقہ ہے پروپیگنڈہ کا وہی استعمال کیا - بلا ضرورت محترم پرائم منسٹر کا نام لیا گیا اور یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ ٹرائبلس کے لئے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں - اس میں بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے - جو آنکڑے جارج صاحب نے دیئے ہیں وہ خود اس بات کے ثبوت ہیں کہ کیا ہماری سرکار نے پچھلے تین سالوں میں کیا ہے اور کیا کرنے کی ضرورت تھی - مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے ہماری کورنسٹ تو بالکل اس کے مطابق ہو گئی ہے اور

[شری وشید مسعود]

اس کے مطابق عمل کر رہی ہے -

"غالب خستہ کے بغیر کونسے کام بند ہیں
روئیے زار زار کیا کیجئے ہائے ہائے کیوں"

یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو تو اس ملک میں مرنا ہی ہے روزآنہ جن لوگوں پر بار بار گولیاں چلتی ہیں جن کی موت ہوتی ہے ان کے بارے میں یہاں چرچا کیوں کی جاتی ہے - اس طریقے کا ایتمچھوٹ ہمارے کچھ ساتھیوں نے یہاں دکھانے کی کوشش کی ہے -

ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ترائبلس کو آخر کیا شکایتیں ہیں جن کو دور کرنے میں ہم ناکام رہے ہیں - اگر آپ اس کی تواریخ دیکھیں تو بستر کے جو راجہ تھے پروین چندر بھنج دیو ان کو محل کے اندر جا کر پولیس نے فائرنگ کی تھی اور اس وقت بھی یہی بات کہی تھی کہ ترائبلس وہاں پر پولیس کے اوپر حملہ کرنے کے لئے تیاری کر رہے تھے اور جہاں پر بھی یہ واقعہ ہوا ہے ترائبلس کے اوپر زیادتی اور ظلم ہوا ہے وہاں پولیس نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ پولیس کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری ترائبلس کر رہے تھے -

اس گھٹنا میں وہاں کیا ہوا تھا - ترائبلس چاہتے یہ ہیں کہ ان کی تہذیب اور تمدن برقرار رہے - لیکن تہذیب اور تمدن تب برقرار رہ سکتا ہے کہ جب ان کے اندر دوسرے انٹرفیئرینس نہ کریں - جیسا کہ میرے قابل دوست مانکے صاحب نے بتایا اندرا ولی، میں بھی اب سے دس بارہ سال پہلے کافی زیادہ لگ بھگ ۸۰ فیصدی تعداد ترائبلس کی تھی لیکن آج وہاں دو تین فیصدی ترائبلس کی تعداد رہ گئی - ایسی صورت میں ان کو اپنی پوری تہذیب کے ختم ہونے کا احساس ہوتا ہے اور بڑی زور کرنے کے لئے ان کو لڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے - میں اپنے دوست سے بالکل متفق نہیں ہوں جو انہوں نے فرمایا کہ ترائبلس کو منع کیا تھا ۱۴۴ لگو تھا اور ان کو کہا کہ کہیں اور جا کر سبھا کر لیجئے - بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جو لینڈلارڈس ہیں اور وہ وہی لینڈ لارڈس ہیں جنہوں نے ان ترائبلس کی زمین کو چھین کر اپنے قبضہ میں کر لیا ہے اور ان کو بھکاری بنا دیا ہے ان کو جب پولیس سے مل کر اجازت دے دی گئی اپنی میٹنگ کرنے کی تو انہوں نے پولیس سے مل کر دوسری میٹنگ اپنی وہاں پر اریننج کی اس کا بہانا بنا کر اس میٹنگ کو کینسل کرنے کی بات بالکل آخر میں کی اور نتیجہ یہ ہوا کوئی بھی اگر اس صورت میں ہوتا ترائبلس ہی کیا اگر میں یا کوئی اور بھی پولیٹیکل

اس کے بعد ایمرجینسی کے زمانے میں انہیں لوگوں نے ان کی عورتیں سب اٹھا لیں - اتفاق کی بات کہ ۷۷ع کا زمانہ آیا اور اس سے نجات ملی... (انٹرپریشن) ... یہ ریکارڈ پر ہے یہ کوئی اپنی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں -

اب کی مرتبہ کیا ہوا ۱۴ جنوری اس سال انہوں نے کہا کہ اب کی مرتبہ ہمیں پوری فوج اکٹھی کرنی چاہئے ۵۰۰ آدمیوں کی - پھر ایک سامنے مقابلہ کیا جائے ایک ایک گاؤں میں جا کر - نتیجہ یہ ہوا کہ شہادا سے کچھ ۶ میل دور پھر دوبارہ ۱۴ جنوری دو گولی چلی اور ۴ ٹرائبلس زخمی ہوئے - پھر وہی رپورٹ آئی - پولیس سے مل گئے بڑے بڑے لینڈ لارڈ اور رپورٹ یہ آئی کہ انہوں نے پولیس پر حملہ کیا تھا لہذا ہمیں اپنے ڈیفنس میں گولی چلانی پڑی - اور رام سیوک سنگھ مہاراشٹر کے جو کہ انکوائری پر گئے انہوں نے ۱۶ تاریخ کو اسمبلی میں بیان دیا کہ ٹرائبل کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں تھی پولیس نے بلا وجہ گولی چلائی - تو یہ پوزیشن ہے - اور صرف یہی معاملہ نہیں ہے ہر معاملے میں ایسا ہی ہو رہا ہے - ہم تو چاہتے ہیں کہ پارٹی پالیٹکس سے اوپر اٹھے لیکن اور لوگ نہیں چاہتے ہیں - ابھی اوکھلا کی لڑکی کا ہی پارٹی ہوتی یا کوئی کمیونٹی ہوتی چاہے کتنی ہی کمزور وہ کیوں نہ ہوتی اگر اس کو اس طرح سے سپورٹ کرنے کی بات کی جاتی تو وہ ضرور ایسا کہتی کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہئے اور وہی انہوں نے کہا کہ ہم تو کریں گے جلسہ - کیونکہ ہمارا پہلے سے طے تھا اور جب انہوں نے پبلس فل میٹنگ کی تو ان کے اوپر گولی چلا دی - پھر وہی اسٹوری بیان کر دی گئی کہ وہ تو انہوں نے پولیس پر حملہ کیا تھا -

مجھے یاد آ رہا ہے شاید جارج صاحب کو بھی یاد ہوگا سن ۱۹۷۴ع میں شہادا میں ایک بہت بڑی میٹنگ کی گئی تھی لینڈ لارڈس کی طرف سے اور اس کے اندر یہ طے کیا گیا جس میں ایک شوگر فیکٹری کے مالک جو اتفاق سے رولنگ پارٹی کے ممبر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ۲۵ لاکھ روپیہ اکٹھا کرنا چاہئے اور اور ٹرائبلس سے جو ہمارے کریٹ کاٹ لیتے ہیں اور جو ہماری زمینوں پر حالانکہ وہ زمین گرام سماج کی تھی اپنے جانور چراتے ہیں ان سے بچنے کا کوئی اپائے کرنا چاہئے - اس کے لئے ہر گاؤں میں دو دو تین تین آدمی رکھنے چاہئے فوجی اور انہوں نے راجستھان سے اور دوسری جگہوں سے لوڈھے اور پٹھان بلا لئے - وہ دو دو تین تین ہر گاؤں میں چھوڑ گئے -

ریزرویشن ہو جو کہ ان کی گریوانسز کو دور کر سکے -

میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا سمے دیا -]

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति जी, कोई ट्राइबल मरे/या कोई पुलिस का जवान मरे--- यह हमारे लिए बड़े दुःख की बात है। लेकिन मुझे अफसोस है कि श्री जार्ज फर्नांडीस ने अपनी स्पीच में कहीं भी पुलिस के जवानों के मरने का कोई जिक्र नहीं किया और न ही बाघड़ी जी ने अपने भाषण में ऐसा किया। । कोई भी मरता है तो उस पर सभी को दुःख होना चाहिए। जहां तक इस हादसे का सवाल है, जब आदिवासी मीटिंग करने के लिए गए तो पुलिस वालों के समझाने पर वे वापिस भी चले गए थे लेकिन फिर वापिस आकर उन्होंने पुलिस जवान की हत्या कर दी और फिर उसके बाद झगड़ा शुरू हो गया।

जैसा कि फर्नांडीस साहब ने साफ तरीके पर यहां कहा है कि 1959 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया था जिसके जरिए पाबन्दी लगाई गई थी कि आदिवासियों की जमीन कोई खरीद नहीं सकेगा लेकिन उस समय से लेकर आज तक कितनी ही जमीनें लोगों ने आदिवासियों से खरीद ली हैं। उस कानून के हिसाब से वह जमीनें आदिवासियों को वापिस की जानी चाहिए। मैं समझता हूं जब तक वह जमीनें वापिस नहीं होंगी उनके दिलों में रंजिश बनी रहेगी। जो कानून बना था वह जमीनें खरीदने वालों को तो मालूम है लेकिन बेचने वालों को मालूम नहीं था, उन लोगों ने जान-बूझ कर वह जमीनें खरीदी हैं इसलिए वह सारी जमीनें आदिवासियों को बिना मुआवजे के वापिस की जानी चाहिए।

[شری رشید مسعود]

معاملہ چل رہا تھا اس کو اٹھا لیا گیا - ہمارے ایک منسٹر صاحب نے جب ان سے کانگریس (آئی) کے لوگ ملنے کے لئے گئے اور کہا کہ اس میں کانگریس (آئی) کے لوگ بھی شامل ہیں تو ان سے انہوں نے کہا کہ اس میں مسز گاندھارتے اور سکندر بخت بھی آ گئے ہیں اس لئے یہ پارٹی پالیٹکس چل رہی ہے - ... (انٹرپشن) ...

ابھی تو آٹھ ملٹ پورے نہیں ہوئے ہیں - میں ختم کر رہا ہوں میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ پرابلم بہت سیریس ہے - اس معاملے میں زبانی ہی نہیں پریکٹیکل طریقے سے ہم کو پارٹی پالیٹکس سے اوپر اٹھنا چاہئے ہمارے ٹرائبلس اپنی تہذیب اور تمدن برقرار رکھنا چاہتے ہیں - تری پورہ کا ہی معاملہ ہے جہاں ۱۹۷۱ع میں چار لاکھ کی آبادی میں ۳ لاکھ ٹرائبلس تھے اور آج ۱۷ لاکھ کی آبادی میں ۴ لاکھ ٹرائبل ہیں - ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے - اس کو روکنے کے لئے قدم اٹھانے چاہئے - اور اندرا بلی کا جو مسئلہ ہے اس کی ہائی کورٹ جج کے ذریعہ سے جوڈیشیل انکوائری ہونی چاہئے تاکہ صحیح فیکٹس سامنے آ سکیں اور جو لوگ ذمہ دار پائے جائیں ان کو سخت سزا دی جائے - دوسرے لوکل ایشو پر کوئی ایسی کمیٹی بنائی جائے جس میں ٹرائبل کا زیادہ تر

जरूरी है कि हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने बंधुआ मजदूरों को विमुक्त करने का प्रोग्राम बनाया और देहात के गरीब लोगों को बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कर्जा देने का भी प्रोग्राम बनाया जिस पर अमल भी हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं फर्नांडीस जी की पार्टी क्या कर रही है? राजनीतिक दल अगर देहातों में जाकर काम न करें सिर्फ पार्लमेंट और असेंबली में भाषण ही देते रहे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर कोई किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है तो मैं उसका जिक्र यहां नहीं करना चाहता जैसे कि बहुगुणा जी की एक पार्टी है लेकिन बाकी जितनी पार्टीज हैं जिनकी कुछ न कुछ बेस है उनको गांवों में जाकर हरिजन आदिवासियों के लिए कुछ काम करना चाहिए ताकि आगे ऐसी घटनाएं होने से रूकें।

जैल सिंह जी के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जो चंडीगढ़ में रहता था उसका मकान इमर्जेंसी के समय में गिरा दिया गया था इस संबंध, में मैंने उनको लिखा था तो उन्होंने जांच पड़ताल करवाकर जिस अफसर ने गिराया था उससे पैसे वसूल करके, जिसका मकान गिराया गया था, उसको पैसा दिलवा दिया। यह हम लोगों का काम है कि जहां कहीं भी हमला होता है, तो उसको एप्रोपिएट अथोरिटी को बताना चाहिए, अगर नहीं बताया गया और इस को खाली पोलिटिकली एडवानटेज लेने के वास्ते यहां पार्लियामेंट में भाषण देने आते हैं, तो यह फिजूल है और उनका यहां बैठना फिजूल है।

इतना कहते हुए, सभापति जी, आपको धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Shri Bhogendra Jha.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): On what basis?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) सभापति जी आप कभी तीन मिनट और कभी दो मिनट का अंकुश लगा रहे हैं, लेकिन इसके पहले।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Either you follow the party position.. I requested you and you did not agree.

MR. CHAIRMAN: You are going to get a chance.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I want to get it according to my party position. (*Interruptions*) So did I. I also want to go. (*Interruptions*) No, no, you are doing it arbitrarily, I must say. (*Interruptions*) I asked you something and you made me to sit down.

SHRI BHOGENDRA JHA (Madhubani): Mr. Chairman, Sir, today, I will thank my friend Mr. George Fernandes and Mr. Mani Ram Bagri for having a discussion under 193. We are discussing atrocities against the adivasis, aboriginal Indians who have been subjected to persecution, subordination and oppression on issues of language, culture, economy and all other aspects of life in our country. Today when they are also trying to assert their democratic rights, the large army of usurers are openly resorting to illegal dealing throughout the country particularly among the advasis who are not allowed to stand on their own legs economically mainly because of illegal usury prevalent in our country.

The Government that has been ruling this country uptill - now has not been able to enforce the Money Lending Act in any part of the country, in any village of the country and particularly in any area where the adivasis are there. Similarly as you know, culturally, they inherit certain things which are pre-Aryan. Through the ravages of time, they have been dis-

[Shri Bhogendra Jha]

torted, changed but not entirely altered. For example, the women among them are not so oppressed as among the feudal dominated society among the non-adivasis. The adivasi women have comparatively enjoyed more freedom and quality than among others, and that is inherited from pre-Aryan Indian culture, pre-Aryan Indian society where there was no feudal system in our country, though no ruler no ruled. In that sense, they give us something, some inherent strength to our democracy because they manage their life, social life on some democratic basis. So, taking all these things into account, in this House no one will deny that atrocities are not being committed against the adivasis; no one will deny that there are some basic causes and the remedy has to be also basic. But what can be the remedy? One thing I would like to suggest and this House to consider is whether it is time or not that the adivasis majority areas in the country is formed into a separate State.

I come from Bihar; but even in Bihar, there are areas where the adivasis are in a majority. Why can they not form a State? Why can they not be allowed to rule in the adjoining areas of Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, a vast belt in Rajasthan and Gujarat, in this part? I want to know whether this House will consider it or wait for a day when there will be a large scale massacre of adivasis. And they as human beings also do retaliate about which Shri Ram Gopal Reddy was just complaining. When they are oppressed and murdered on a mass scale it is not to be expected that they will go on tolerating one sidedly just like dead persons. They are expected to retaliate also. So, will we wait for that period? We should not. So, I submit that with regard to the States the annexation of lands of Adivasis must be prevented through special measures by the Centre. There are laws in almost all the States but they are openly being violated with the connivance and even support of the officials, the political and administrative set up that we have inherited from the British. So their land had to be protected Usury should be banned. There cultural and linguistic traditions should be developed and the majority Adivasi areas should be allowed to form separate States within the Indian Union. They should be allowed to develop. This will not harm the unity of the country but the areas which I have mentioned near Bihar, Orissa, Madhya Pradesh and Rajasthan where these areas are in the centre of the country should be developed. In such a situation, I should like to submit that this House today or hereafter should consider certain measures so that we are in a position to say that no atrocities against Adivasis have been committed. The atrocities will remain as long as the capitalist system remains. The special nature of the atrocities and the special nature of the operations should be contained to prevent them.

2.00 hrs.

SHRI GIRIDHAR GOMANGO (Koraput): Thank you for calling my name. My friends who participated in this debate have contributed a lot for the tribals. Being a tribal I would like to put forth our grievances and viewpoints and the feelings in this House for the consideration of the Government. You will find that if you send an anthropologist to a tribal area, he will say that the tribals are museum specimens. If you send a historian he will say something from the historical point of view. If you send a money lender he will exploit them. A politician will politicalise our issues. That is the fate of our tribals.

A number of committees have submitted their reports for the welfare of tribals but so far we have not achieved our objective for which the commissions and committees have been constituted. The problem which we are considering is a very vital problem and it concerns us. Fourteen tribals have been killed by the Police.

What was the defect and who is responsible for it? That is a judicial matter. But I will confine myself to the discontent among the tribals. What is the reason for discontentment among the tribals? Land alienation, indebtedness, forest policy, excise policy, nonpayment of minimum wages, bonded labour and displacement of tribals due to major projects, these are the reasons for tribal discontentment. We have to check the exploitation of the tribal population. So far a number of committees have recommended various measures in this regard. The land disputes and the economic problems, and police atrocities and other problems have been dealt with by the Commission for S.C. and S.T. which had submitted its report recently. That is the white paper about the problems of Harijans and Adivasis. That should be discussed. If you see that report you will see how many cases of atrocities have been committed on tribals and Harijans. In this context when we are discussing this problem I would recall my resolution which was discussed in this House and in that debate nearly 36 members participated. On the same lines I had moved that resolution urging the Government to take up the economic development of tribals areas and also to curb atrocities.

I should like to know in this context—I will take only a few minutes more—what is Government's approach towards tribal development and tribal problems? I ask, what is the attitude of the Government? What is the attitude of the officers who are responsible for the welfare of tribals? What is the allocation made so far by the Centre and the States for the administration of tribal areas? What allocations have been made to improve the quality and character of tribals? What are the achievements? These are the main issues which exert our mind.

Always we put forth the problem before this House. We are representing the tribals. A number of times this question has been raised. Please give us time to express our viewpoints. I am speaking from my heart. This is my feeling, the feeling of the tribal people.

I would like to make a few suggestions. What have you done about the creation of a separate department for tribal development in the Home Ministry, which was recommended by the Dhebar Commission 20 years ago? You please tell us whether you are going to do something for the inclusion of tribal development in the concurrent list. It was suggested by the Commissioner that legislation regarding alienation of tribal land should be included in the Ninth Schedule. You have not done it so far. The allocation of funds for tribal development which was to be made in the fifth plan was done. We are in the sixth plan and already two annual plans are over. But still the Ministry-wise allocation of funds and programmes has not been done.

Coming to the question of reservation, there are some people who have some reservation in their minds about it, and they think that, if reservation is provided in the Constitution, the people will get opportunities for employment. Please remove that reservation in their minds Then the problem will be solved.

Regarding the administrative set-up in the tribal areas under the fifth and sixth schedules, the role of Governors, the role of the President, the Centre and States are there. Is that administrative set-up sufficient or do you want to strengthen it according to the constitutional provision?

Sir I am saying all this not to blame anybody but to place our problems before the House, so that the Government of India may think on this line as to what has been done, what is to be done and what has not been done in regard to tribal development so far. If others speak for us, some people

[Shri Giridhar Gomango]

will take it has a suggestion. But if the tribal people speak for themselves, it is treated as reaction. I want to submit that actually it is not reaction, but only a suggestion for action.

With these words, I conclude.

*SHRI R. K. MHALGI (Thane): Mr. Chairman, Sir, it is unfortunate that even after 33 years of independence, the miserable plight of the Adivasis continues. They cannot live peacefully in the forests and we have failed to protect their lives and property. Many stories of their miseries can be narrated, but I don't propose to discuss it in detail for want of time. The figures of atrocities committed on the adivasis as recently announced by Government in this House prove the magnitude of the problem. During 1978, 2452 cases of assaults on the tribals were registered. In the year 1979, 2160 cases of atrocities took place and in 1980 more than 3000 cases of crime against the adivasis have been registered.

The current year has witnessed terrible atrocities on the adivasis and even the stone hearted would be moved.

The "Current" dated the 25th April, 1981 reports a "Gang rape on 12 Adivasi girls". 'Blitz' of the same date has a news item "rape and murder of tribal girls". A signed article by Dr. Manoj Mathur in both these journals has brought out the facts. I want to know the reactions of the Government towards the article.

It is not enough to cite examples of atrocities on the tribals. The reasons for these atrocities should be thoroughly investigated. One of the causes of this problem is land disputes. The land of Adivasis is occupied by non-tribals who are being backed by the Government. This is most unfortunate. There are some middlemen who grab the amount sanctioned for tribal welfare schemes; it never reaches to the tribals. Even if they receive it is a meagre amount on which they cannot survive. This leads to frustration.

Many disputes have taken place because of tribal women who are subjected to rape. Many problems have cropped up regarding the distribution of loans to the tribals. Some measures need to be taken urgently to solve their problems.

The first Five Year Plan commenced in 1952. We have already implemented 5 five year plans. Mr. Fernandes referred to Jawaharlal Nehru's speech. If we want to realise the dream of Panditji, it is necessary to evaluate the Five Year Plans and assess the work done for the Adivasis. A document detailing the Plan allocations, the targets fixed and the achievement in the matter of tribal welfare should be presented to the House. Only after such an evaluation, will we know the work that needs to be done.

The State Governments have passed several acts relating to tribal welfare; it needs, however, to be seen whether the laws are properly implemented. Law Commission should bring out a report regarding the legislations passed by the State Governments on tribal welfare and their implementation. It should be placed before this House.

Many State Government have set up Forest Development Corporations. The Central Government gives vast sums to them. We should know whether they have properly utilised Central assistance for tribal welfare plans.

It is often pointed out that the subject of tribal welfare should be discussed above party level, the problem will not be solved by allegations and criticism by one political party against an another. I fully agree with this view of hon. Member Shri Ram Gopal

*The original speech was delivered in Marathi.

Reddy. I am of the opinion that Government alone should not be held responsible for solving the problem of tribals. It is the duty of society and MPs to cooperate with the Government.

The political parties are reminded of tribal areas only at the time of elections. But what is required is dedicated workers who are prepared to work in tribal areas. I may refer to an institution named "Kalyana Ashram" who took inspiration from the RSS and is doing pioneering work in the tribal areas. I feel that such voluntary organisation should come forward to render service.

SHRI KAMALUDDIN AHMED (Warangal): Mr. Chairman, Sir, I will confine myself to the Indervalli incident. It was an unfortunate incident, which should not have occurred and our sympathies are for those innocent people who lost their lives in the police firing.

We may have our own subjective attitudes and emotions. But I would submit that this incident should not be used for the expression of our subjective attitude. If we agree on the facts, it will help us to arrive at correct conclusions. If we decide to agree on the salient features of this incident, I think we will be doing justice to ourselves and we will be able to really take up some measures.

It is a fact that for quite some time the so-called People's War Group had been very active in that area. In fact, from Hyderabad to Khammam, all along the Godavari, this Group has been very active. This Group has been instigating the people, tribals and also non-tribals, to indulge in violence. It is also a fact that recently the State Government had started taking up some developmental measures in these areas. Because of the apprehension that they will lose the ground, this Group had indulged in three such incidents, before this Indervalli incident. On those three previous occasions, the police did not resort to any such strong measures which, in fact, encouraged these people to repeat such incidents.

It is also a fact that they had instigated the tribals to hold a meeting at Indervalli village, which is essentially a non-tribal village. The population of this village is only 4,000 whereas the mob which had gathered to hold the meeting was about 5,000, according to the reports. Apprehending disturbance, the district authorities imposed section 144. Defying this section 144, they still gathered there and tried to hold the meeting.

Another fact which has to be admitted is that a police constable was pierced to death and the SP of Police was attacked. It is only after that that the Revenue Divisional Officer, who is also the executive magistrate, permitted the police to resort to firing.

It has also to be admitted that except the so-called People's War Group, there was no involvement of any political party in the entire incident. It was purely a law and order matter, the magistrate was there and the incident has taken place in his presence.

An enquiry has been held, the Home Minister of the State Government has visited the place and a magisterial enquiry has been ordered. After the enquiry is completed, the whole facts will come to light. Anyway, this was a very unfortunate incident, which we should all condemn.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): Sir, there is not very much left for me to say and I will, therefore, confine myself to the wider issues.

Sir, Mr. Fernandes must be complimented for bringing this important topic before Parliament, but I wish that the time allotted for it was more during the peak hours of our parliamentary assembly and not at this far end.

[Dr. Subramaniam Swamy]

Sir, in my constituency in Bombay one would have thought that there are no Adivasis. I do not even know what the term 'Adivasi' connotes. 'Adi' means first, 'vasi' means settler. I do not know whether the Adivasis are the first settlers. The correct term that should be used is 'Vanavasi', not 'Adivasi'. But that is another matter .

In a part of my constituency which is called Vihar Lake, there are Adivasis there and in the city of Bombay they live as they have been living for thousands of years. It is not only the question of remote villages, but out in the city of Bombay you have a cluster of Adivasis. So, the question today is: What are the wider issues that we have to consider? There are atrocities going on all the time, there is no doubt about that. But what is it that comes out of it? Ambedkar said very rightly, and I quote from a publication brought out by the Akhil Bharat Anusuchit Jati Parishad of which the President is Mr. Yogendra Makwana. Sometimes he does good work also and he brought out a publication called *Constitutional Dynamics of the Reservation Policy* and in that there is a quotation from Ambedkar which rightly says:

> "On the 26th January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. We must remove this contradiction at the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy..."

Today if you are seeing atrocities against the Scheduled Castes or Scheduled Tribes.. (*Interruptions*). But Mr. Makwana very kindly through his publication published this extract for ignorent people like me.

As long as this contradiction remains, there are bound to be atrocities and that is actually what we should address ourselves.

I am shocked at the national reaction of some sections on the reservation policy in general. What is the achievement of the reservation policy? This pamphlet and many others and the past debates have mentioned how few jobs for Scheduled Castes and Scheduled Tribes—in fact I will not make any distinction between the two—how few jobs in Class I and Class II have been available to them. We talk about reservations as if it is a major concession made to them. But we must remember that this reservation only applies to Government jobs. In the private sector which accounts for 85 per cent of the jobs in the country there is no reservation and in the remaining 15 per cent of the jobs in Class I and Class II the reservation is only 3 per cent and 5 cent or something like that. Therefore, the whole question today is one of viewpoint. There is a psychology that has been built up and that is why what we have to ask ourselves is not whatever small minimal safeguards that we have brought, but are they not under seige today? Are they not under attack today? And who is responsible for that?

I find today a very pernicious argument floating around in the country that there should he a national policy on reservations a national consensus on reservations. What does that mean? The national policy and the national consensus—it was all settled in 1946, 1947 and 1948 and by the time the Constitution came in 1950 it had been settled. There is no question of reopening that question. The moment anybody save that there should be a national policy in my opinion, in the heart of hearts of that person there is that feeliing that this reservation should go. That is the lurking suspicion behind that and therefore, I would say that whoever calls for this national policy is in fact against

reservation. And that this call for national policy is, in my opinion, a camouflage for an anti-reservation approach and that is what we have to object. I have seen some people say that there should be reservation but not in promotion. Why not? Why should it not be? How can you say-once the people enter at a lower level and thereafter there should be equal opportunity. Therefore, even on the issue of promotion there is no re-opening of the question. I am also amazed to see in the press 'a call for white paper on the reservation'. What do you mean 'white paper on reservation'. This is not a question of war and you want to know how many casualties have taken place. The Scheduled Castes Commissioner is there. He is producing annual reports. They have had all things tabulated. Why do you need a white paper? That means in your heart, you are against reservation. That is why you are bringing all this red herring. It is a method of side-tracking the issue and, therefore, I would say there should be....

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi): You go and ask your party President.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: If my party President has said this, he is not....

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: He made a statement that there should be no reservation so far as promotions are concerned. He is in a position to explain that statement.

SHRI JANARDHANA POOJARY (Mangalore): Propagating in battles. Vajpayee's party is also propagating. *(Interruptions)*

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: We will find out in a few days what the policy of Janata Party is because the National Executive is meeting in Bangalore. Reservation policy of the Janata Party will be reaffirmed. I do not want to go by what the individuals here and there say.

MR. CHAIRMAN: This question relates to a different thing.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: No. This reservation has got to do with the matters of Scheduled Castes. Just because you have name like 'Panigrahi', it does not mean that you should say all this to me. It is a central issue.

SHRI JAI PAL SINGH KASHYAP (Aonla): People from all over India want clarification from both the parties.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: That clarification of Janata Party's policy will come out of the National Executive meeting very soon.

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): What is that Janata Party, I want to know?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Well, as long as you know what Adivasi is that is good enough. As long as Mr. A. K. Roy knows what the law of the country is, that is O. K. There is a great doubt on both the points. Therefore, this question has to be centrally attacked. It is no use saying there are atrocities here and atrocities there, suspend that sub-inspector, transfer that Superintendent of Police, that is not the issue. The issue today is fundamental. Questions are being asked which should not be asked. Fundamentals have been settled. Once the concessions have been given on reservation, those cannot be withdrawn. They cannot to questioned. If some States are not giving as much as other States are giving, you force those States to give equal to other States. You cannot say that there should be national policy. What do you mean by 'national policy'? If the other States are not giving you penalise those States. You tell them to give at par with those States which are giving more. That is the question that we should be addressing to ourselves.

The danger of regression is there. When the meeting of the Leaders of

[Dr. Subramaniam Swamy]

the Opposition was called by Shrimati Indira Gandhi, I opposed even the concessions given by the Gujarat Government on the carry over matter. Why? Because, in this issue there is danger of regression. Once you start, you slide all the way back. Then you yield on a point which looks on abstract terms. There may be injustice, in abstract terms it may be. I do not agree even there. May be, there is an arguable point there. If you yield there, then the issue becomes 'anti-reservation'. If you yield on anti-reservation, very soon they will be anti-harijan. If you yield on 'anti-harijan' there will be pro-caste system. *Varna vivastha* will come back again in its full form. That is why I had not to yield there itself. We are in a slippery slope and we have got to keep where we are. The moment we take one step back we will have to take thousand steps back. What we achieved in thirty years, we will have to give up in thirty days. That is the danger of the danger of regression. I would say it is for this House to reaffirm, not its commitment to the policy, that policy is already there, but to go on giving reservation. We read and we listen Ramayana. We know all those stories. We know that Ram lost his kingdom for fourteen years. Sita was kidnapped. Could we listen to it every year? Why do we listen to it? Because human mind is like that. Certain things are to be hammered in. So, the rights of the harijans, the rights or the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the rights of the tribals have to be hammered in every time and there should not be even an inch of ratreat on any point on merit or no merit.

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : सभापति महोदय, इंद्रवली में जो घटना घटी है, वह एक बहुत दर्दनाक घटना है और लगता है कि आदिवासियों और हरिजनों की समस्या के बारे में राज्य सरकारों की पकड़ धीरे-धीरे ढीली होती जा रही है। इस बीच में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वे आदिवासी क्षेत्र में हों और चाहे हरिजनों से संबंधित हों। जब इन समस्याओं या दुर्घटनाओं के बारे में हम लोग संसद या एसेम्बलियों में चर्चा करते हैं, तो इस बात की कोशिश करते हैं कि मलहम लगा कर लोगों या सदस्यों के मन में जो तात्कालिक रिजेंन्टमेंट है, उसको कम किया जाए। परन्तु सरकार से मेरा निवेदन है कि अब समय आ गया है कि हम इस मर्ज की तह में जाएं, ताकि उसका इलाज किया जा सके।

मेरी ऐसी मान्यता बनती जा रही है कि आदिवासियों की जो समस्या है राज्य सरकारें या तो उसके प्रति उदासीन होती जा रही है या वे इसको नौकरशाहों के भरोसे छोड़ती जा रही हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ़ मिनिस्टर साहब ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि यह सारा मसला लैंड को ले कर खड़ा हुआ है। 24 अप्रैल के हैदराबाद के हिन्दू अखबार में उनका यह स्टेटमेंट आया है:-

"The Chief Minister said, the forest produce should be purchased directly by the Government from the tribals. If we pay them the correct price, then the exploitation of the tribals will end."

दूसरी ओर पुलिस ने कहा है कि केवल आतंकवादी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं मेरा निवेदन है कि यह कह कर कि आतंकवादियों ने लोगों को उकसाया, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। सरकार को इस में जाना चाहिए कि यह समस्या क्यों उत्पन्न हुई।

कल तक मुझे केन्द्रीय सरकार पर विश्वास था कि आदिवासी क्षेत्र और हरिजनों की समस्याओं के बारे में उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बी० बी० सी० को

बस्तर में एक डाकुमेंटरी बनाने की जो अनुमति दी है, मैं उस सवाल को पिछले तीन-चार दिनों से संसद में उठाने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि किस ढंग से शब्दों के जाल में बी बी सी ने भारत सरकार की नाक में चूना लगाया है। भारत सरकार ने बी बी सी को बस्तर में अबूझमाड़ में डाकुमेंटरी बनाने की अनुमति दी है, जो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टिड एरिया है और जो मेरी कांस्टीट्युएन्सी है। मैं चाहूंगा कि मैंने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है, गृह मंत्री उसको मंजूर करें और इस विषय पर बहस के लिए तैयार हों।

मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आप हमें जंगल में रहने दें, हमें अपने ढंग से जीने दें। इस तरह की परमिशन दे कर आप हमारी जिन्दगी में, हमारे जीवन में, एक व्यवधान लाना चाहते हैं। इस बारे में जो समाचार आ रहे हैं, उन्हें देखते हुए भारत सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह इस मामले को साफ़ करे, क्योंकि भारत सरकार ने जो आवजर्वर पयवेक्षक भेजा था, वह उसने वापस ले लिया और राज्य सरकार का पर्यवेक्षक भी वहां से चला गया। और केवल एक वहां के जिलाधीश रह गए जिन को बी बी सी वालों ने ओछे ढंग से अपने साथ कर लिया, है, उन्होंने जांच कर के रिपोर्ट दे दी कि वहां पर ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं हुई है जब कि जिलाधीश वहां कहीं पिक्चर में नहीं हैं। इस तरह से गैर जिम्मेदाराना ढंग से केन्द्र सरकार ने भी बी बी सी को परमिशन दिया है। इसीलिए हमारी यह मांग हैं खासतौर से, समय-समय पर जो हम करते रहे हैं कि केन्द्र सरकार में भी आदिवासियों और हरिजनों के अलग से विभाग हों ताकि ऐसे बहुत से मसले हैं जिन पर समय-समय पर संसद में विचार किया जा सके।

ये जितने भी मसले हैं और जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उस में तीन बातों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा—एक तो शोषण, दूसरे जमीन और तीसरे जंगल। शोषण के बारे में सरकार की तरफ से कुछ प्रयास किए जा रहे है चाहे सोसाइटी हो, या एसोसियेशन या दूसरी संस्था हो, ये सभी संस्थाएं आप की नौकरशाही के चक्करों में पड़ी है जिस से जो काम किया जाना चाहिए वह काम हो नहीं रहा है। इसीलिए असंतोष बढ़ रहा है।

जमीन के मामले में हर राज्य सरकार ने अपने-अपने कानून बनाए हैं। इसके बावजूद भी जिस ढंग से प्रभावशाली रूप से इस के ऊपर अमल होना चाहिए वह हो नही पा रहा है। जंगल के बारे में हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हर साल राज्य सरकार जंगल की नीति में परिवर्तन करके आदिवासियों के अधिकार और उन की जो सुविधाएं है उस में कटौती करती जा रही है और धीरे-धीरे नौबत आ गई है कि 74 में जब कारपोरेशन की अनुमति भारत सरकार ने दी उस समय भी हम लोगों ने अपनी आपत्ति जाहिर की थी, पिछली 21 तारीख को बस्तर में पूरे आदिवासियों की मीटिंग हुई जिस में हम लोग भी गए हुए थे, वहां सारे आदिवासियों ने कहा कि इस जिले से कारपोरेशन के अधिकार खत्म किए जाने चाहिए क्योंकि आप ने एक संस्था खड़ी कर दी लेकिन जैसा कि महालगी साहब ने कहा इन की कार्य प्रणाली पर भी रिव्यु होना चाहिए, उस का पुनर्निरीक्षण होना चाहिए कि यह कहां तक उस क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से काम कर रही है या नहीं,

[श्री अरविन्द नेताम]

यह देखना चाहिए। निस्तार के संबंध में जो सुविधाएं थी उन को धीरे-धीरे कर के खत्म कर रहे हैं। जंगल से उन का जीवन बहुत जुड़ा हुआ है। आज जंगल में रहने वाले आदिवासी बाहरी हो गए, आउटसाइडर हो गए और सारी जिम्मेदारी फारेस्ट डिपार्टमेंट की हो गई। सारा रिजेंटमेंट इस बात का है।

आन्ध्र प्रदेश में जो हमारे साथियों ने कहा कि आज जो वहां गिरिजन कारपोरेशन है, एक समय था कि उस के सम्बन्ध में बहुत अच्छी रिपोर्ट थी कि वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से भी काफी अफसर इस बात को देखने के लिए गए कि वहां का जो गिरिजन कारपोरेशन है वह अच्छा काम कर रहा है, परन्तु आज क्या हो गया ? आज उसी का परिणाम है कि चीफ मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि अगर हम उनको ठीक ढंग से कीमत दे सकें तो बहुत बढ़िया होगा।

अन्त में एक बात कह कर समाप्त कर देना चाहता हूं। इस सब का एक ही निदान है। अगर आज से 20 साल पहले भारत सरकार और सारी राज्य सरकारों ने ढेबर कमीशन की सिफारिशों को अच्छे ढंग से लागू किया होता, उन का पालन किया होता तो आज यह स्थिति नहीं होती। मेरे कुछ साथियों ने कहा कि अलग से कमीशन बनाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आज भी 20 साल हो गए फिर भी कोई देर नहीं हुई है, उसी ढेबर कमीशन की सिफारिशों को फिर से लागू करना चाहिए। एक बात से मैं आगाह कर देना चाहता हूं, बस्तर के बेलाडीला में, दल्ली राजहेड़ा में आज भी हड़ताल हो रही है और वहां के सारे जो मजदूर हैं, आदिवासी और हरिजन हैं वह असंतुष्ट हैं, भविष्य में हो सकता है कि कुछ अनहोनी घटना हो सकती है। मैं गृह मंत्री जी को अभी से आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर इन की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो फिर से कुछ न कुछ अनहोनी घटना हो सकती है। बिहार में तो हो ही रहा है। जिस ढंग से आदिवासियों के साथ वहां व्यवहार हो रहा है, झाबुआ में जो हुआ, ये सब के सब एक चेन हैं, आन्ध्र प्रदेश से ले कर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और बंगाल के सारे जो ट्राइबल बेल्ट हैं उन में यह हो रहा है, यह बड़ी गंभीर समस्या है। अब वक्त आ गया है कि केन्द्र सरकार इन क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उन के सम्बन्ध में फिर से विचार करे, राज्य सरकारों पर इस को नहीं छोड़ना चाहिए।

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): Mr. Chairman, Sir, we are here not to defend and not to offend but only to make some honest introspection.

Coming from the Chhota Nagpur area of Bihar, I know what treatment the tribals get from the State Government, the Central Government, the political parties and the press and from this House.

Three statements have come on the recent firing in Andhra Pradesh. One statement has come from the Minister for Tribal Welfare: another statement has come from the Chief Minister; and the third statement has come from the Home Minister of Andhra Pradesh. I was shocked to see that all the Congress MPs repeated the statement made by the Home Minister; they avoided uttering the statement made by the Chief Minister of Andhra Pradesh and also their Minister for Tribal Welfare. What the Chief Minister has said is this—this has been reported in the *Statesman*:

"'Anjiah Attributes Tribal Trouble to Land Disputes' The Chief

Minister, Mr. T. Anjiah, Yesterday (23/4) attributed the trouble in Adilabad district where 13 tribals were killed in a tribal village (Indervalli) in a police firing on Monday to a long-standing land dispute.....Unless we restore the land to the tribals, the trouble will continue."

This is what the Chief Minister is saying, and their MPs are afraid or reluctant to repeat in the House.

Now, what their Tribal Welfare Minister is saying...

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: I said it.

SHRI A. K. ROY: You did not say.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: I said that the land must be restored to them.

SHRI A. K. ROY: The Tribal Welfare Minister, their Minister—not belonging to our Party or any other Party, not the so-called Naxalite Group which they have been repeating again and again..(*Interruptions*) has said this:

"The Minister for Tribal Welfare told the newsmen that the previous Government..."

That is also Congress-I Government.

"..the previous Government had issued an order allowing the non-tribals to possess small holdings in the tribal areas reserved by the tribals. The previous Government had issued the order in contravention of the Land Transfer Regulation Act, allowing the non-tribals to occupy the agency land...The present Government was considering withdrawal of the order in view of the restlessness among the tribals..."

That means, the wrong action of your Government created the situation—as accepted by your Minister—which led to the firing. The firing took place. Not a single house of the non-tribal, landlord, was attacked. No sabotage was made. The tribals were only armed with stones, and when they threw the stones, the stones injured some policemen. After the firing, in the melee one policeman was killed. This is the attitude we are having. One thing I would like to say is that it is not only a question of reservation. Reservation is only the tip of an iceberg. Even with reservation we are killing, but cheering, the tribal people. It questions the very foundation of our society, our attitude. The stark and agonising discovery in my experience shows that we *Indians* do not consider the tribal people as Indians, not even as human beings. That is the stark discovery of my experience. Had any other fourteen people been killed in any part of India, there would have been a political earthquake. But here nobody was concerned with that. Only some hon. Members created a scene here and they forced this discussion.

Similar type of things happened in Gua. I personally went to investigate there. You would be surprised to know that there also 14 people were officially killed. You would be shocked to know that only four people were killed on the spot and the rest ten people were killed in the hospital. The Adivasis had carried the injured to the Gua hospital; they were dragged out from the beds because the hospital is situated just in front of the BMP camp. In front of the doctors and nurses, they were killed on the verandah of the hospital; the dead bodies remained there for 24 hours.

The Tribal Minister of Bihar who had gone to Gua was not allowed to enter Gua because no tribals are made Ministers. My point is this. Even if the persons from the tribal communities or the Harijan communities are *made ministers, they have no powers.* That is the stark reality. They would not come within the power structure. (*Interruptions*)

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: What about West Bengal? Are there no troubles?

SHRI A. K. ROY: Troubles are everywhere. There is variation in degree only. The troubles are there. I do not want to go into details. What I say is that the harijans are the periphery of the power structure. The tribals are outside the power structure. That is one of the points. So, I want to give two suggestions. The first and most immediate suggestion is that whenever the tribal people are killed in any part of the country, a Committee of Members of Parliament should go there and investigate into that and then within seven days they should give their report. Their suggestions should be binding on the State Govesrnment.

My second suggestion is: we must give the tribals their homeland, their autonomy. They should be directly with the Ministry they are going to constitute, namely, the Ministry for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

This is a long-term remedy. If we have a short-term remedy of having a judicial enquiry, that is no remedy at all. This will continue endlessly and, ultimately, the people will forget when the conclusions are reached by them.

MR. CHAIRMAN: Shri Shiv Prasad Sahau. Be brief and take three minutes

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से नियम 193 के तहत बिहार के छोटा नागपुर के, रांची एवं मध्य प्रदेश, उड़ीसा के आदिवासियों पर हो रहे जुल्म व अत्याचार के सम्बन्ध में संक्षेप में माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आज आदिवासियों का मनोबल कल से कहीं अधिक गिरा हुआ है। कल का निर्भीक आदिवासी केवल कुल्हाड़ियों से शेरों का शिकार करने वाला, अंग्रेजी सेना की बन्दूकों को अपनी रहस्यमयी शक्तियों से जाम कर देने वाला आदिवासी एक मामूली सिपाही को देखकर क्यों जंगलों व पहाड़ों में छिप जाता है ? सभ्य मनुष्यों से दूर रहने में ही वह अपनी भलाई क्यों समझता है ? वास्तव में उसे लगता है कि उसके पारम्परिक मूल्यों से उसे अलग किया जा रहा है। सौ में से एक भी आदिवासी ऐसा नहीं मिलेगा, जो पूरी तरह स्वस्थ हो, उन की नसल दिनोंदिन कमजोर होती जा रही है। बड़े दुःख के साथ में, श्रीमन्, मैं आपके सामने आदिवासियों पर हो रहे जुल्म की कुछ सच्ची कहानी पेश कर रहा हूं। साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि भविष्य में सरकार के प्रति उनकी आस्था और विश्वास जगे। मैं चन्द उदाहरण उन पर हो रहे अत्याचार के सम्बन्ध में पेश कर रहा हूं, उम्मीद है मकवाना जी बुरा नहीं मानेंगे, मैं पहले ही उनसे क्षमा चाहता हूं।

मैंने माननीय राज्य मंत्री, गृह विभाग, श्री मकवाना साहब को चन्द महीने पहले श्रीपत्ति राम एवं उनके अन्य कुछ 16 सहयोगियों के सम्बन्ध में ईंट-भट्टे के मालिकों द्वारा जुल्म ढाए जाने के सम्बन्ध में उनके हस्ताक्षरित आवेदन पत्र अपने सिफारिश के साथ दिया था। 23-3-81, डी० ओ० नं० 915/एम० एस० (एच०)/वी० आइ० पी०/81 राज्य मंत्री का उत्तर आया कि "मैं इसे दिखवा रहा हूं।" दूसरा पत्र श्री रामवृक्ष का था, जिसमें मैंने इट्टा-भट्टे के मालिकों द्वारा शोषण की चर्चा की थी, श्री मकवाना साहब को तिथि 26-3-81, डी० ओ० नं० 999/एम० एस० (एच०)/वी० आइ० पी०/81 उत्तर आया कि "मैं इसे दिखवा रहा हूं"। पुनः मैंने श्री उमरावं साधु कुजूर विधायक बिहार का

पत्र अपने सिफारिश पत्र के साथ हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिला में एक ग्राम बिकवाई है। वहां रांची (चुटिया मोहल्ला) के निवासी गुप्ता होटल का प्रबन्धक एवं कर्मचारी सर्वश्री सुदर्शन गुप्ता एवं जय प्रकाश गुप्ता ने रांची के 9 लड़कियों को ले जा कर बेच दिया है। उन मासूम बच्चियों को बरामद कराने के लिए मैंने मकवाना साहब से अनुरोध किया था। इस में मकवाना साहब का पत्र ता० 2-4-1981 डी० ओ० सं० 1114/एम एस(एच) बी० आइ० पी० /81 प्राप्त हुआ जिस में इन्होंने लिखा है --"मैं इसे दिखवा रहा हूं।" पुनः मैंने रांची जिले के लोहरदगा अनुमण्डल के ग्राम कुटमू की एक नाबालिग लड़की "बसन्ती" के सम्बन्ध में, जो दिल्ली के मि० धर्मपाल, मकान न० 10756, नालेवाली गली, मानिक पुरा, दिल्ली-6 के पास है जिस को वह ट्रक से उड़ा कर तथा झूठा प्रलोभन दे कर एवं दिल्ली ला कर अपने यहां रखे हुए हैं, को बरामद कराने के सम्बन्ध में मैंने तथा कार्तिक उरांव, राज्य मंत्री, संचार विभाग, भारत सरकार ने भी गृह विभाग को लिखा था। इस सम्बन्ध में भी उत्तर प्राप्त हुआ कि "मैं इसे दिखवा रहा हूं।"

श्रीमन्,, कितना बयान करूं, इस तरह के सैंकड़ों अत्याचार, व्यभिचार तथा शोषण के मामले भरे पड़े हैं। बहुत सारे पत्र मैं समय-समय पर माननीय प्रधान मंत्री जी एवं गृह विभाग को लिखता रहा हूं तथा सदन में भी बोलता रहा हूं, किन्तु महीनों गुजर गये कार्यवाही कुछ नहीं हुई। मैं गृह विभाग को सावधान कर देना चाहता हूं कि इस तरह की स्थिति सिर्फ सूबे बिहार में ही नहीं है, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों से आदिवासी लड़कियों की खरीद, बिक्री एवं हर तरह से उन का शोषण किया जा रहा है।

एक अन्य समस्या की ओर भी मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं-- हमारे प्रदेश में कोल-फील्ड्स हैं, कोयल-कारो योजना चल रही है, स्वर्ण-रेखा डैम प्रोजेक्ट चल रहा है तथा हटिया आदि स्थानों में आदिवासियों की जमीन इन योजनाओं के लिए ली जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जिन की तीन एकड़ से अधिक जमीन ली जाएगी उन को नौकरी देंगे, उस से कम वालों को नौकरी नहीं दी जायगी। मैं पूछता हूं--कौन ऐसा आदिवासी-हरिजन है जिस के पास तीन एकड़ से अधिक जमीन है। इस तरह से हमारे 95 प्रतिशत से अधिक आदिवासी-हरिजन बेकार होते जा रहे हैं, एक तरफ उन की जमीन ली जा रही है दूसरी तरफ़ उन को नौकरी में नहीं लिया जा रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे छोटा नागपुर और उड़ीसा के आदिवासी इन्हीं सब कारणों से बहुत क्षुब्ध हैं और बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। मैं गृह मंत्री जी को सावधान करना चाहता हूं कि उन की नौकरी की समस्याओं के प्रति सरकार समय रहते चेते, अन्यथा आगे क्या होगा, मैं नहीं जानता। हमारे आदिवासी एम० ए० और बी० ए० पास कर के बैठे हुए हैं लेकिन उन को नौकरी नहीं दी जाती है, हर तरफ़ भाई-भतीजेवाद का बोल-बाला है, जिससे बेकारों की भयंकर फौज खड़ी होती जा रही है।

आप बैंकों की स्थिति को देखिए-- वहां पर जब भी कोई लोन के लिए जाता है तो सब से पहले पूछेंगे कि कहां से आये हो। जब वह बतलाएगा कि अमुक जाति का हूं तो उस को धक्के दे कर बाहर निकाल दिया जाता है। बिना पैसा दिये बैंकों में कोई काम नहीं होता है। इस लिए मेरा सुझाव है कि आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाये जो

[श्री शिव प्रसाद साहू]

उन के रीति-रिवाजों को समझते हों। अन्यथा इस तरह की वारदातें हमेशा होती रहेंगी। सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट द्वारा प्रान्तीय सरकारों को उन के विकास के लिए अरबों रुपया दिया जा रहा है, लेकिन होता क्या है ? प्रान्तीय सरकार से वह रुपया चल कर जिले में आता है, जिले से ब्लाक स्तर पर आता है और वहां तक पहुंचते-पहुंचते आधा रुपया आदिवासियों के नाम से हमारे जो कुम्भकरण उच्चाधिकारी लोग हैं उन के पेटों में चला जाता है। इस पर सरकार को कड़ी निगाह रखनी चाहिए।

हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जंगल भरे पड़े हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां बांस, बाक्साइट, ताम्बा और बहुत सी चीजें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन आवागमन के साधन नहीं हैं, रेलवे लाइन नहीं है जिससे उन का उपयोग हो सके। यदि वहां पर रेलवे लाइन का विकास किया जाय, तो बांस की मदद से कागज बनाने के कारखाने खोले जा सकते हैं। हमारे जो आदिवासी काम के लालच में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की ओर भाग रहे हैं उन को वहीं पर रोजगार मिलेगा, उन का भागना रुक जायगा। जिस तरह से आज उन का शोषण और उन के साथ व्यभिचार हो रहा है, वह रुकेगा। यदि आदिवासियों का कल्याण करना है तो सही मायनों में कीजिए, नहीं तो आदिवासियों का असन्तोष बढ़ रहा है और वह बारूद की दीवार पर बैठता जा रहा है। इसलिए समय रहते हमारी सरकार चेत जाए।

SHRI CHITTA BASU (Barasat): Sir, I wish to draw the pointed attention of the House to a particular development in regard to the atrocities being committed on the Adivasis. There is a growing collusion between the law enforcement authorities and the vested interests existing in the rural areas. This is a very, very crucial point, In the case of Adilabad there is also this sort of collusion between the Police and the vested interests of the locality, in order to deprive the tribals of their legitimate right to land.

Sir, I wish to quote from the Editorial of the *Times of India* dated 24-4-81. It has got a significance and so I quote. It says:

> "One difficulty in accepting such an *alibi* (banning of tribals as well as non-tribals) at its face value is that the Police, as well as non-tribal vested interests in Andhra have often sought to curb even perfectly legal activities of the Organisations agitating for the economic amelioration of tribals".

I would not like to explain it, as it is sufficiently clear even legitimate and peaceful agitation of tribals for land and for higher wages are suppressed; they are not allowed; in these cases the Law Enforcement authorities and the vested interests act in unison. Very peculiar arguments are being advanced. They say that there is a growing activity and increasing activity of extremists and because of such "increasing activity" of extremists in these areas, merely because of such a pretext, the Police wants all licence to kill anybody as they like. This is what happens. This is what happened in this case also, Sir. This is what happened in Gua. This happened in almost all areas where tribals have risen up and demanded land. Your so-called sub-plan and component plan are only Paper plans. This is there only to hoodwink the people. The major and the crucial question is the question of 'Land'. Wherever land problem has been solved somewhat satisfactorily like in Kerala and West Bengal, this kind of atrocity is not found on a large scale. I don't say that it has been solved satisfactorily. But at least some effort has been made by the Government and when such an effort is made by the Government, this kind of collusion between law and enforcement authorities and vested interests

against tribals and other oppressed sections of the society does not generally take place. This is my respectful submission.

And here I would like to point out that in the Andhra Act there is a provision which forbids the transfer of land of tribals to non-tribals under all circumstances. This is an improved Act. But I find that this kind of an Act is not available in other States. I would admit it. Because under all circumstances transfer of land from the tribals to non-tribals should be banned. Sir, even your State does not possess that kind of legislation, If I am correct.

MR. CHAIRMAN: There is a legislation.

21 hrs.

SHRI CHITTA BASU: Therefore, a law of this nature that the land transfer from the tribal to non-tribal under all circumstances should be enacted. It is a very important legal step. But the whole question that this has not been implemented is not going to be solved and cannot be solved unless the entire attitude of the Government and the law enforcing authority is changed. Therefore, I would only make 2 or 3 suggestions. It apears that the Government agrees to have those views. In the course of the reply to a question, the Government had said that the land occupied a crucial position in the matter of tribal problem. Therefore, I would suggest that in order to solve this land hunger of the non-tribals, all legislations relating to the alienation of land should be reviewed and enough and adequate compensation should be given to them so that the benefit of this legislation can be made available to the tribals. My second suggestion is that there should be monitoring cell attached to the Home Ministry to see the actual implementation of the land alienation Act for the tribals. My third suggestion is that there should be a compulsory direction from the side of the Government that adivasis who have been deprived of their land because of the Government's acquisition of land for development or for setting up industrial units should not only be provided with adequate compensation but their sons and daughters should be given employment in the industrial units which are coming up there. I think there is a sense of revolt and upheaval among the tribals in all parts of the country. I think the Government and the House will take due notice of this upheaval and the Government in its wisdom should take necessary measures.

MR. CHAIRMAN: Now, we have taken more than 3 hours. There are still 2 or 3 Members to speak. The hon. Minister would take about 25 minutes. Therefore, I would give two minutes to each of you.

श्रीमती विद्या वेंकटपति (विजयवाड़ा): सभापति महोदय, मैं आप के सामने इस विषय में कुछ प्वाएंट रखना चाहती हूं। मेरे से पहले जो माननीय सदस्य बोले, वे तो चले गये हैं। मैं यही कहना चाहती हूं कि आंध्र प्रदेश के इन्द्रावल्ली में जो यह प्रॉब्लम हुआ है, ऐसी प्रोब्लम्स सारे देश में और प्रदेशों में होती रहती हैं और हो रही हैं। हमारे देश में बहुत से प्रदेश हैं और कई प्रदेशों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। यह बात भी हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी।

मैं बेसिकली एक प्वाएंट आपके सामने रखना चाहती हूं। हमारे देश में बहुत सी पोलिटिकल पार्टियां हैं। जब कि यह प्रोब्लम इकोनोमिक और सोशल प्रोब्लम है और इसको इकोनोमिकल्ली और सोशल्ली लेन चाहिए लेकिन होता यह है कि जब ऐसी घटना या दुर्घटना हो जाती है तो उसको पोलिटिकलाइज्ड कर दिया

[श्रीमती विद्या चमूपति]

जाता है । हमारी पोलिटिकल पार्टियों में जो लोग काम करते हैं या और जो लोग दूसरी पार्टियों में काम करते हैं वे इन आदिवासियों को सुधारने के बजाय उनको गवर्नमेंट के खिलाफ एन्करेज करते हैं, हमारी पार्टी के खिलाफ एन्करेज करते हैं। हमें ट्राइबल प्राब्लम को एक सोशल प्राब्लम की तरह लेना चाहिए । हमारी सरकार श्रीमती गांधी की लीडरशिप में इन लोगों को बहुत सहायता दे रही है, लेकिन जो जो उनके लिए काम किया जाता है, उसको ये लोग भूल जाते हैं और जो नहीं हुआ है उसको कहना शुरू कर देते हैं। यह किसी पार्टी की समस्या नहीं है, इसलिए जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं, सब को मिल कर आम-जनता को सुधारने के लिए प्रयत्न करने चाहिएं । उनकी उन्नति के लिए हम सब को सोचना है । ट्राइबल लोगों की उन्नति के लिए क्या-क्या काम करना है—क्या कार्यक्रम बनाने हैं, पार्टी वर्कर्स को यह सोचना चाहिए ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय सभापति जी, जितने हल्के ढंग से आदिवासियों की समस्या को लिया जा रहा है, यह तो इसी बात से प्रतीत होता है कि हमारे माननीय ज्ञानी जी, कैबिनेट मिनिस्टर को यहां रहना चाहिए, लेकिन वे यहां नहीं हैं । इससे ऐसा लगता है कि सरकार की इस ओर ज्यादा तवज्जह नहीं है । यह इस बात से भी स्पष्ट है कि इस तरह की बहस हमेशा रात को ही होती है । पूरे देश को पता नहीं लग पाता और न ही पूरे रूप से बहस हो पाती है ।

सभापति जी, शास्त्रों में लिखा है कि आदिवासी और शूद्र की हत्या करने पर उतना ही पाप लगता है. जितना एक नेवले या मेंढक को मारने पर लगता है ।

आचार्य भगवान देव : कहां लिखा हुआ है ? ये गलत कह रहे हैं ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप: "मनुस्मृति" में लिखा हुआ है । अगर नहीं लिखा होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा ।

आज एक तरफ तो आदिवासियों की सुरक्षा और उन पर होने वाले अत्याचारों को ले कर चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ आदिवासियों के आरक्षण के खिलाफ जो एंटी रिजर्वेशन आन्दोलन-कारी हैं उनको बेल करके जुलूस निकालने की आज्ञा दी गई है । मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार एक एण्टी कांस्टीट्यशन एजीटेशन करने वालों को कैसे आज्ञा दे दी गई ? वे आदिवासी भी जुलूस निकालना चाहते थे, मीटिंग करना चाहते थे, उनको आपने गोलियों से भून दिया, दर्जनों लोगों को मार दिया और उनका जो लोग हित नहीं चाहते हैं उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं । इससे सरकार की नीयत पर शक होता है । इसलिए मेरा कहना है कि तुरन्त एक पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की जाए और जहां-जहां आदिवासी-हरिजनों, कमजोर और पिछड़े वर्गों, मुसलमानों आदि की हत्याएं हुई हैं, चाहे वे हत्याएंपुलिस ने की हों, सब मामलों की जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ केस दाखिल करके चार्ज-शीट लगा कर अदालतों में उनका ट्रायल होने दीजिए, ताकि हरिजन-आदिवासियों को पता लगे और उनमें विश्वास पैदा हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री दलबीर सिंह (शहडोल): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक दो सुझाव देना चाहता हूं । यदि सही माने में मकवाना जी हरिजनों का हित चाहते हैं तो उनके पास फाइल पेंडिंग है, इसके

बारे में मैंने पहले भी कई बार इस सदन में बात कही है । भारत-शासन में आदिवासी और हरिजनों के लिए केवल एक डिवीजन काम कर रहा है । मैं उन अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं डा० भूपेन्द्र सिंह जी और श्री कृष्णन जी, लेकिन उनके पास भी स्टाफ नहीं है। इसलिए आज आपको सदन में यह आश्वासन देना होगा कि इसके लिए एक डिपार्टमेंट आप कायम करेंगे, जिसके जरिये हिन्दुस्तान के हरिजन और आदिवासियों का कल्याण हो सकता है ।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो इंद्रावली में दुःखद घटना घटी है उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि हर जगह हरिजनों को यह कह कर मारा जाता है कि ये नक्सलाइट हैं, डकैत हैं, इस प्रकार इन इनोसेंट लोगों को मारा जाता है, तो क्या कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी मारा गया है ।

जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन सब घटनाओं के लिए आप जवाब-दार हैं ।

आज सारे मध्य प्रदेश में अखबारों में एक बात प्रकाशित हो रही है—"बी० बी० सी० द्वारा मध्यप्रदेश में आदिवासी जोड़ों का नग्न छायांकन" मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बस्तर में "घोटुल" आदिवासियों की एक संस्था है, जिसमें यंग लड़के-लड़कियां रहते हैं । बी० बी० सी० के लोग एक गिरोह बनाकर वहां पर गए । यह कहा गया कि उनके नग्न चित्र नहीं लिए जाने चाहिये । लेकिन आदिवासियों के जो वहां जोड़े लड़के लड़कियो के थे उनको पैसे का लालच दे कर, उनके कपड़े उतरवा कर उनकी फिल्में ली गई हैं और ये फिल्में हिन्दुस्तान से ले जा कर, ब्ल्यू फिल्में बाहर दिखाई जा रही हैं । आप सो रहे हैं । मि० मरवाह को भेजा गया लेकिन उसको क्लैटर की साजिश के कारण वहां से लौटा दिया गया । क्लैटर को वहां से हटाया जाना चाहिए ।

वहां पर मामला बड़ा कम्पलिकेटिड हो गया है । बड़ा भारी असन्तोष वहां फैला हुआ है । बी० बी० सी० वाले वहां कैसे गए ? डायरेक्टर ने साफ रिफ्यूज कर दिया और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को हम नहीं मानते हैं, भारत सरकार ने हमें भेजा है, हम फिल्म लेंगे । झाबुआ का-यह प्रश्न है । बिहार के भी इसी तरह के प्रश्न हैं, गुजरात, आंध्र के भी हैं । मामला बहुत बिगड़ता जा रहा है । समस्या बहुत बिगड़ती जा रही है ।

यदि आप आदिवासियों और हरिजनों की भलाई चाहते हैं तो आपको चाहिये कि आप डिपार्टमेंट कायम करें । विश्वस्त सूत्रों से मुझे पता चला है कि निर्णय के लिए फाइल आपके पास पड़ी हुई है । क्यों आप डिपार्टमेंट कायम नहीं कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि आप आश्वासन दें कि आप शीघ्र ही डिपार्टमेंट को यहां कायम करने जा रहे हैं ।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : 33 साल की आजादी के बाद भी हरिजनों और आदिवासियों की समस्याओं पर हम सदन में विचार विमर्श कर रहे हैं। 33 साल का अनुभव बताता है कि इनकी समस्याओं पर जितना समय इस हाउस में खर्च किया जाता उससे कई गुना ज्यादा अत्याचार इन पर बढ़ते जा रहे हैं । सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक सभी से उनका शोषण होता आ रहा है । 33 साल से वही लोग इन पर हावी हैं जो इनको वर्षों से सताते आ रहे हैं । मेरा

[श्री जगपाल सिंह]

अनुरोध है कि संविधान के अनुच्छेद 46 में जो प्रावधान दिया गया है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज हैं उनको आप पूरा नहीं करते हैं तो आजादी का करोड़ों लोगों के लिए कोई मतलब नहीं होगा, उसके कोई माने नहीं होंगे । संविधान के के अनुसार उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति आप करें वर्ना स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी । ये लोग जानवरों से भी बदतर जिन्दगी बिता रहे हैं । कपड़ा, दवा, शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति से ये अछूते हैं । अगर अब भी आपने उनके लिए कुछ नहीं किया तो जो आक्रोश और क्रोध उनमें पैदा होगा उसको आप रोक नहीं पायेंगे ।

एक घटना की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मध्य प्रदेश से अभी दस हजार लोगों को, आदिवासियों को नेपाल जबर्दस्ती ले जाया गया । सदन में जब चर्चा हुई तब मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम ने ज्यादातर लोगों को वापिस बुला लिया है । लेकिन उड़ीसा के दस हजार आदिवासी गुलाम बना कर मुल्क से बाहर ले जाए गए हैं और उन से जो गलत ढंग के धंधे कराए जा रहे हैं उनकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये । यह बहुत ही खराब चीज है । अगर आपने उनकी ओर ध्यान न दिया तो वह दिन आने वाला है और आप रोक नहीं पाएंगे जब लोग अपनी समस्याओं का निदान हिंसा के रास्ते से निकालने के लिए सड़कों पर निकल आएंगे ।

सभापति महोदय : आनरेबल मिनिस्टर ।

श्री जगपाल सिंह : हाउस में कोरम नहीं है । मैं इस सवाल को इसलिए उठाना चाहता हूं कि हरिजनों और आदिवासियों की समस्याओं पर विचार में जब हो रहा है तो आप सदन से उपस्थिति को देखें । कोरम का न होना बहुत हैरानी की बात है । कोई सदन में है ही नहीं । विरोधी और रूलिंग पार्टी दोनों को आप ले लें । मैं समझता हूं कि इस मामले को सीरियसली नहीं लिया जाता है । रूलिंग पार्टी के लोगों को चाहिये था कि वे कोरम पूरा रखते । कोरम का अभाव बड़ा अखरता है । स्टेट मिनिस्टर ही बैठे हुए हैं । गरीब लोगों के मामले पर चर्चा होती है तो न्यूज कवरेज भी नहीं होता है । इसलिए यह बड़ा सीरियस मामला है । आज ही नहीं हमेशा ऐसा होता है । जब हरिजनों और आदिवासियों की समस्या पर विचार होता है तो कोई कोरम नहीं होता है ।

सभापति महोदय : आप बोल चुके हैं ।

श्री जगपाल सिंह : मंत्री जी के जवाब को कैसे जाने दें जब कोरम ही नहीं है ।

श्री मनीराम बागड़ी : उन्होंने कोरम का सवाल उठा दिया है, आप उसके ऊपर क्या कहेंगे ।

सभापति महोदय : वह प्रेस नहीं कर रहे हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : होम मिनिस्टर सदन छोड़ कर चले गए हैं । आप देख लें कांग्रेस पार्टी के कितने लोग बैठे हैं । सदन से इतने लोग क्यों चले गए हैं ? इसी तरीके से हमारा खालिस्तान वाला मामला था ।

आचार्य भगवान देव : जिन लोगों ने सवाल यहां खड़ा किया है, उनकी पार्टी के ही कितने व्यक्ति यहां उपस्थित हैं ? अपना

चेहरा आइने में स्वयं देखें, उसके बाद बात करें । उनके कितने फालोअर्स यहां पर हैं, जिन्होंने यह चर्चा खड़ी की है ? (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : होम मिनिस्टर क्यों नहीं हैं । उनके इस्तीफे की मांग की गई थी, लेकिन वह खुद ही नहीं है और मकवाना साहब को बैठाकर चले गये । जब इन्होंने प्रश्न उठाया है तो इस पर आप क्या करेंगे ?

श्री जगपाल सिंह : जब भी हरिजन और आदिवासियों पर चर्चा होती है तो ऐसे समय पर होती है जब न प्रैस है, न टैलिवीजन है, न रेडियो है और न यहां पर कोरम है ।

आचार्य भगवान देव : यह रेडियो और टेलीविजन पर समाचार चाहते हैं, इन लोगों को इस समस्या का कोई ख्याल नहीं है । ये सिर्फ रेडियो और टेलिविजन की बात चाहते हैं ।

MR. CHAIRMAN: Is Mr. Jagpal Singh pressing for quorum?

श्री मनीराम बागड़ी : हम चाहते हैं, यह मामला गंभीरता से लिया जाये । सभापति जी, आप क्यों जबर्दस्ती कर रहे हैं, आप इनकी बात को क्यों दबा रहे हैं ? आप कोरम कराइये ।

श्री जगपाल सिंह : आप हमारी भावनाओं को देखिये ।

Yes; I am pressing.

MR. CHAIRMAN: Let the quorum bell be rung.

(*Interruption*)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. The quorum bell is ringing—Please ring the quorum bell again. We are ringing the quorum bell for the second time. There is no quorum. The quorum bell is going. on ringing—

Nothing is going on record. There is no quorum. Nothing is going on record. We are ringing the quorum bell—

The second bell for the quorum is being rung.

If we find that there is no quorum, according to rules, we shall proceed—

As there is no quorum, the House stands adjourned to meet tomorrow at 11 A.M.

21.25 hrs.

The Lok Sabha then adjjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 29, 1981/Vaisakha 9, 1903 (Saka).

GMGIPND—Job III—767 LS—29-7-81—890.